● वर्ष-4
● अंक-175
रायपुर, रविवार
02 मार्च 2025
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» सबसे ज्यादा ब्यूटी टाइटल जीत चुकी हैं...

इंडस्ट्री डायलॉग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय का उद्योगपतियों को आमंत्रण

नई औद्योगिक नीति से 1.23 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त

रायपुर। आप छत्तीसगढ़ आइए, निवेश करिए और विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहभागी बनें। विकसित और समृद्ध छत्तीसगढ़ को समर्पित हमारी नई उद्योग नीति लागू होने से अब तक राज्य सरकार को 1 लाख 23 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। राज्य सरकार न्यूनतम प्रशासन-अधिकतम प्रोत्साहन, उद्यमियों को निवेश अनुकूल माहौल और हर संभव सहयोग दिए जाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नवा रायपुर में आयोजित इंडस्ट्री डायलॉग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने वाली भारत सरकार की महती योजना रैंप का प्रदेश में शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 09 लाभार्थियों को 2 करोड़ 21 लाख से अधिक, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य संस्करण योजना के तहत 3 लाभार्थियों को 55 लाख से अधिक तथा राज्य में निवेश करने वाले 16 निवेशकों को इनविटेशन टू इन्वेस्ट पत्र वितरित किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प रखा है। उनके संकल्प के अनुरूप छत्तीसगढ़ को विकसित करने छत्तीसगढ़ विजन 2047 तैयार कर इस दिशा में लगातार काम कर रहे है। उन्होंने कहा कि ईज आफ डूइंग बिजनेस के तहत अनुमति, अनुमोदन और नवीनीकरण की प्रक्रिया हमने काफी आसान कर दी है, जिससे प्रदेश में निवेश आकर्षित हो रहे हैं। श्री साय ने बताया कि हमारी सरकार उद्योग जगत की सुविधा के लिए नये औद्योगिक पार्क स्थापित कर रही है। इनके तैयार होने के बाद यहां तेजी से निवेशक अपने उद्योग लगा सकेंगे। प्रदेश सरकार ने 7 नये लघु औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की है तथा 4 बड़े औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना प्रक्रियाधीन है। बस्तर के नगरनार स्टील प्लांट की स्थापना के चलते सहायक ईकाइयों के लिए बड़ी संभावनाएं बनती हैं। इन्हें स्थान देने के लिए नगरनार के पास नियानार में 118 एकड़ भूमि में नये औद्योगिक पार्क की स्थापना की उन्होंने जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद से हम रायपुर, दिल्ली और मुंबई में इंवेस्टर्स कनेक्ट कार्यक्रम कर चुके हैं जिसमें बड़ी संख्या में निवेशकों ने छत्तीसगढ़ में निवेश की इच्छा जताई है। नई औद्योगिक नीति के लागू होने के बाद अब तक 1 लाख 23 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले है और 50 से ज्यादा उद्यमियों को निवेश हेतु प्रमाणपत्र भी सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज पदार्थों से समृद्ध है। हम बिजली सरप्लस स्टेट हैं। सेंट्रल इंडिया में होने के कारण कनेक्टिविटी देश के सभी हिस्सों से शानदार है और हमारी नीति और नीयत ने प्रदेश को निवेश के लिए आदर्श स्थल बना दिया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने एआई, आईटी, डाटा सेंटर, रोबोटिक्स जैसी नई संभावनाओं के साथ ही फार्मास्युटिकल, रेडीमेड गारमेंट सेक्टर में निवेश के लिए नई औद्योगिक नीति में विशेष प्रोत्साहन दिए जाने की जानकारी दी। श्री साय ने सेमी कंडक्टर, डाटा सेंटर और एआई आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेश के रजत जयंती वर्ष का जिक्र करते हुए छत्तीसगढ़ की वित्तीय यात्रा की जानकारी भी साझा की। उन्होंने बताया कि पिछले 25 वर्षों में प्रदेश की जीएसडीपी 20 गुना बढ़कर 5 लाख करोड़ हो गई है। उन्होंने बताया कि पिछले 25 वर्षों में प्रदेश के बजट का आकार भी बढ़ा है और अब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की दिशा में भी लगातार काम कर रहे हैं।

तैयार थे पकवान, जेलेंस्की-ट्रंप की बहस से बिगड़ा जायका

अमेरिका ने बिना लंच परोसे लौटाए यूक्रेन के राष्ट्रपति को

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उप राष्ट्रपति जेडी वेंस और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच हुई जुबानी जंग के बाद असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। मीडिया के सामने 40 से 45 मिनट तक चले इस हाईवोल्टेज ड्रामे ने हर किसी का ध्यान खींचा। मुलाकात के दौरान क्या-क्या हुआ? यह अब धीरे-धीरे सामने आ रहा है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बहस के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और उनके यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल को बिना लंच किए व्हाइट हाउस से जाने के लिए कह दिया गया। दरअसल मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वेंस और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ दोपहर का भोजन करने वाले थे। इसे लेकर खास तैयारियां की गई थीं। लंच को लेकर गाड़ियां व्हाइट हाउस भी पहुंच गईं थीं। पकवान व्हाइट हाउस में सज भी गए थे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस हुई और माहौल बिगड़ गया। इसके बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गए।

ट्रंप और जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में बैठक करीब 40 मिनट तक चली, लेकिन आखिरी के 10 मिनट में बनती बात बिगड़ गई और दोनों नेताओं के बीच बैठक किसी सहमति पर पहुंचने के बजाय तनाव चरम पर पहुंच गया। जिसके बाद मीडिया को कमरे से बाहर जाने के लिए कह दिया गया। जिसके बाद जेलेंस्की प्रस्तावित दोपहर के भोजन में शामिल हुए बिना चले गए। बताया जा रहा है कि यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल पास के ही एक कमरे में करीब एक घंटे तक इंतजार करता रहा। उन्हें लगा था कि ट्रंप लंच पर बैठेंगे तो दोनों नेताओं के बीच बनी तनाव की स्थिति कम होगी और फिर चीजों को ठीक करने का मौका मिलेगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद व्हाइट हाउस की ओर से उन्हें जाने के लिए कह दिया गया। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल बातचीत जारी रखना चाहता था, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। इससे जेलेंस्की और गुस्सा गए और व्हाइट हाउस छोड़कर तुरंत होटल चले गए।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, व्हाइट हाउस ने यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल को लंच के लिए आमंत्रित नहीं किया। उनके खाने के लिए स्प्रिंग ग्रीन सलाद, रोजमेरी रोस्टेड चिकन और क्रीम ब्रुले जैसी खाने की चीजें बनाई गई थीं। जिसके बाद यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल के लिए बनाए गए खाने को व्हाइट हाउस के कर्मचारियों को परोसा गया।

मुख्य मार्गों पर केक काटना पड़ेगा महंगा, जाना पड़ेगा जेल

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सड़कों पर केक काटने का दूसरा मामला सामने आया। मामले पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। वहीं रायपुर कलेक्टर ने हिदायत भी दी है। सार्वजनिक जगहों पर या मुख्य मार्गों या मुख्य चौक चौराहे पर बर्थडे सेलिब्रेशन करना दंडनीय अपराध है।

रायपुर कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने कहा कि सामान्यत: देखा जा रहा है कि हम सिविक सेंस को भूलकर कई बार सड़कों पर जन्मदिन बनाने के लिए निकल आते हैं। सड़क के नियमों का पालन नहीं करते हैं। सड़कों पर अतिक्रमण करने की अवरोध बन जाते हैं। हम सड़क के नियमों का पालन नहीं करते हैं। अवैध रूप से सड़कों पर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं। बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं।

उन्होंने कहा कि कहीं पर भी इधर-उधर पार्किंग में गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जो कि आम जनजीवन को प्रभावित करता है। इसलिए कलेक्टर होने के नाते मेरा आप सभी से निवेदन है कि सड़क सुरक्षा से संबंधित जितनी भी चीज हैं उनका कड़ाई से पालन करें। उन्होंने आगे कहा कि मैं विशेषता बताना चाहता हूं कि अपनी खुशी को आप सार्वजनिक स्थानों पर रोड बीच रोड में जन्मदिन मनाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। उनके खिलाफ जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है, की जाएगी।

उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि ऐसा कोई काम ना करें जो कि उनको और उनके परिवार के लिए कष्ट का कारण बने और समाज के लिए भी कष्ट का कारण बने।

दूसरी ओर रायपुर एसपी डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह ने कहा कि किसी के द्वारा भी मुख्य मार्ग पर या मुख्य चौक चौराहे पर अपना जन्मदिन या पारिवारिक आयोजन किए जाने से लोगों को मार्ग अवरोध होता है। इस प्रकार का कृत किया जाना अपराध के श्रेणी में आता है। किसी भी चौक चौराहे पर अपना बर्थडे के काटना आयोजन करना दंडनीय अपराध है। साथ ही एक माह की सजा होती है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का कृति के जाने पर पुलिस के द्वारा प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की जाती है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि ऐसे सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक मार्ग पर किसी प्रकार का बर्थडे सेलिब्रेशन या केक काटने का कृत न करें। ऐसा करने पर जेल जाने की नौबत आएगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ में शांति, सुशासन और सतत विकास को लेकर चल रही पहल पर केंद्रीय मंत्री से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की दिशा में किए जा रहे प्रयासों और विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी साझा की।

प्रमुख समाचार

परिसीमन और भाषा विवाद के बीच स्टालिन ने बुलाई बैठक

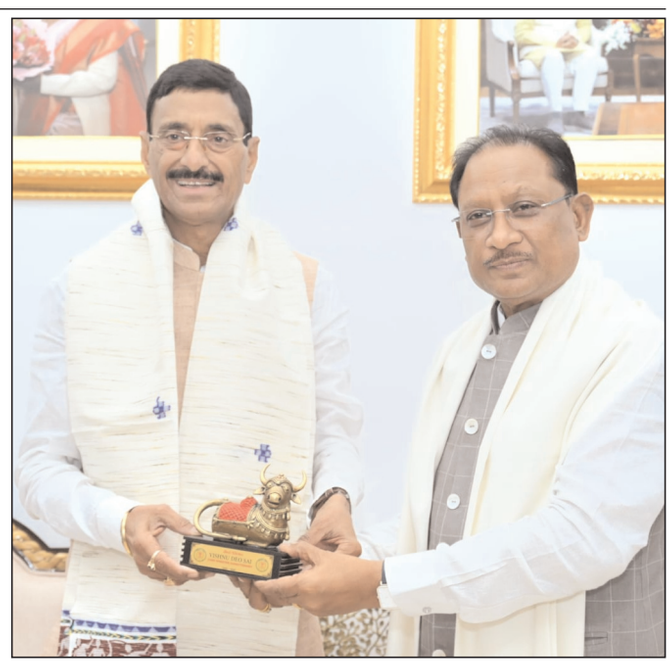

नई दिल्ली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रस्तावित लोकसभा परिसीमन अभ्यास और तीन-भाषा नीति से संबंधित चिंताओं पर चर्चा करने के लिए 5 मार्च को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें 45 राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया है। हालांकि, बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताते हुए बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि उनका फैसला गहन विचार-विमर्श के बाद आया है। एक भाजपा नेता ने कहा कि हमने बैठक में भाग नहीं लेने के अपने कारणों को बताते हुए मुख्यमंत्री को एक विस्तृत पत्र भेजा है। स्टालिन के पत्र में परिसीमन और तीन-भाषा नीति के संबंध में कई सवाल उठाए गए हैं, और हमने प्रति-प्रश्न करते हुए अपनी प्रतिक्रियाएं भी प्रदान की हैं। मुख्यमंत्री की चिंताओं के आधार पर सवाल उठाते हुए, भाजपा ने पूछा, आप किस आधार पर दावा कर रहे हैं कि तमिलनाडु की संसदीय सीटें कम हो जाएंगी? यह जानकारी किसने प्रदान की? यदि स्रोत का खुलासा किया जाता है, तो हम अपने रुख पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार हैं।

अनुच्छेद 136 में हस्तक्षेप संकीर्ण माना गया - धनखड़

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को कहा कि विशेष अनुमति याचिका का प्रावधान एक संकीर्ण रास्ता माना जाता था, लेकिन अब इसके व्यापक इस्तेमाल के कारण मध्यस्थता प्रक्रिया को नुकसान पहुंच रहा है। धनखड़ ने मध्यस्थता मामलों में विशेषज्ञों की आवश्यकता पर भी बल दिया और कहा कि वाणिज्यिक विवादों से जुड़े जटिल मामलों को निपटाने में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां मध्यस्थता पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए धनखड़ ने अनुच्छेद 136 के उपयोग एवं मध्यस्थता प्रक्रिया पर इसके प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा, ''अनुच्छेद-136 के तहत हस्तक्षेप को संकीर्ण माना गया था। कुल मिलाकर इसमें सब शामिल हैं कि मजिस्ट्रेट को क्या करना है, सत्र न्यायाधीश को क्या करना है, जिला न्यायाधीश को क्या करना है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को क्या करना है।'' संविधान का अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय को किसी भी निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए ''विशेष अनुमति'' प्रदान करने की अनुमति देता है।

दिल्ली वासियों को मिलेंगी 1,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें

नई दिल्ली। दिल्ली के नवनियुक्त परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने शनिवार को बताया कि सरकार एक साल के भीतर परिवहन क्षेत्र को लाभदायक बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, राष्ट्रीय राजधानी को इस महीने एक हजार से अधिक इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। एक इंटरव्यू में सिंह ने कहा कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर फिलहाल 235 करोड़ रुपये के घाटे में चल रहा है। परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि सरकार एक रिकवरी योजना पर काम कर रही है और एक साल के भीतर इस क्षेत्र को लाभदायक बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को जनता के लिए अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।सिंह ने कहा कि हमें सार्वजनिक परिवहन में सुधार करने की जरूरत है ताकि लोग निजी वाहनों पर कम भरोसा करें। हमारा पहला कदम दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें शुरू करना होगा, इसके बाद परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए और सुधार किया जाएगा। पंकज कुमार सिंह नवगठित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार में छह कैबिनेट मंत्रियों में से एक हैं। उन्हें परिवहन, स्वास्थ्य और अन्य विभागों के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। परिवहन विभाग के बारे में सिंह ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार अगले छह महीनों में परिवहन क्षेत्र में धीरे-धीरे सुधार करेगी।

लालू परिवार ने बिहार को 15 साल में बनाया खटारा - सम्राट

पटना। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि एक यशस्वी राजनेता को लालू परिवार के गाली देने से उनकी उम्र लंबी हो रही है । वे अभी और 15 साल बिहार की सेवा करते रहेंगे। चौधरी ने कहा कि जैसे 66 करोड़ लोगों को महाकुम्भ आस्था और एकता का सागर दिखा, लेकिन कुछ लोगों को वह फालतू लगा, वैसे ही बिहार में 20 साल में नीतीश सरकार के विकास का शानदार ग्राफ, राजस्व में 15 गुना वृद्धि, 14.5 फीसद की तेज विकास दर और प्रति व्यक्ति आय का 7 हजार बढ़ कर 66 हजार रुपये होना राजद को कबाड़ लग रहा है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने 15 साल में बिहार को जर्जर सड़क, अपहरण उद्योग, बिजली-रहित गांव, जातीय हिंसा और 100 से ज्यादा नरसंहार दिये, उनका परिवार आज विकास का चकाचौंध प्रकाश नहीं देख पा रहा है। चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के सफल नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से बिहार ने गरीबी-अशिक्षा-बेरजगारी और अपराध के अँधेरे से निकाल कर तेज विकास के प्रकाश की ओर जो यात्रा शुरू की है, उसे बार-बार जनता का आशीर्वाद मिलता रहेगा।

बृजभूषण शरण सिंह ने खरीदा एक और हेलीकॉप्टर

गोंडा। कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक और हेलीकॉप्टर खरीदा है। पांच सीटर इस हेलीकॉप्टर का शनिवार को पूजन किया गया। नवाबगंज के विश्नोहरपुर निवासी पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह छह बार सांसद रह चुके हैं। लग्जरी एसयूवी का काफिला लेकर निकलने वाले पूर्व सांसद ने पिछले साल एक हेलीकॉप्टर खरीदा था। अब उन्होंने दूसरा हेलीकॉप्टर खरीदा है। शनिवार को पारिवारिक सदस्यों के साथ उन्होंने हेलीकॉप्टर का पूजन किया। भगवा रंग के इस हेलीकॉप्टर का वीडियो व फोटो पूर्व सांसद ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। आर66 मॉडल वाले इस हेलीकॉप्टर की कीमत से सात से आठ करोड़ के बीच की बताई जा रही है। बलरामपुर सदर के विधायक पल्टूराम ने पूर्व सांसद को बधाई दी है। पूर्व सांसद के निजी सचिव संजीव सिंह ने बताया कि हेलीकॉप्टर होने से अन्य प्रदेशों व सुदूर इलाकों में रहने वाले समर्थकों के यहां आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में समय से पहुंचने में सहूलियत होगी।

–

मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में आगे बढ़े भारत और यूरोपीय संघ

मुंबई। भारत और यूरोपीय संघ ने मुक्त व्यापार समझौता लागू करने की दिशा में आगे कदम बढ़ा दिया है। यह समझौता इस साल के अंत तक लागू हो सकता है।

शनिवार को भारत और यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते के प्रयासों पर चर्चा की। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और यूरोपीय संघ के व्यापार एवं आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफकोविक के अलावा दोनों पक्षों के अधिकारियों ने मुंबई में बात की।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर लिखा कि हमारी चर्चा संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में प्रयासों को तेज करने पर केंद्रित थी। हम आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और समृद्ध भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए तत्पर हैं। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। दोनों पक्ष मुक्त व्यापार समझौते, निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेत (जीआई) पर भी समझौते पर बातचीत कर रहे हैं।

यूरोपीय संघ की प्रमुख ने पीएम मोदी से की थी चर्चा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति व्यक्त की थी। दोनों पक्षों के बीच 10-14 मार्च तक ब्रुसेल्स में एफटीए के लिए दसवें दौर की वार्ता आयोजित होने वाली है। ट्रंप की टैरिफ धमकी को देखते हुए भारत और यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। मौजूदा अनिश्चित वैश्विक आर्थिक स्थिति में भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है। 2024-25 में इसके 6.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है।

2013 में रुक गई थी वार्ता

मुक्त व्यापार समझौते को लेकर मतभेदों के कारण 2013 में वार्ता रुक गई थी। जून 2022 में भारत और 27 देशों के यूरोपीय संघ के बीच आठ साल बाद बातचीत फिर से शुरू हुई। यूरोपीय संघ ऑटोमोबाइल में महत्वपूर्ण शुल्क कटौती की मांग के साथ वाइन, स्पिरिट्स में कर कटौती की मांग कर रहा है। अगर समझौता हो जाता है तो यूरोपीय संघ को भारतीय वस्तुओं का निर्यात जैसे सिले-सिलाए वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, इस्पात, पेट्रोलियम उत्पाद और विद्युत मशीनरी मिलने लगेंगे। जबकि भारत आईटी क्षेत्र के लिए डाटा सुरक्षा दर्जा भी चाहता है।

यूरोपीय संघ के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 137 बिलियन अमेरिकी डॉलर

वित्तीय वर्ष 2023-24 में यूरोपीय संघ के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 137.41 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, इसमें यूरोपीय संघ को निर्यात 75.92 बिलियन अमेरिकी डॉलर और यूरोपीय संघ से आयात 61.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। इस तरह से यह ब्लॉक नई दिल्ली का वस्तुओं के मामले में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

2023 में सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार 53 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भारतीय निर्यात और 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात शामिल है, जो सेवाओं में अब तक का सबसे अधिक व्यापार है। भारत में यूरोपीय संघ का निवेश 117 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है तथा लगभग 6,000 यूरोपीय कंपनियां भारत में मौजूद हैं। यूरोपीय संघ में भारत का निवेश लगभग 40 अरब डॉलर का है।

नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदों ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ

■ डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी रहे मौजूद

धमतरी, दुर्ग, जगदलपुर। दुर्ग नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर अलका बाघमार ने शनिवार को महापौर पद की शपथ ली। इसके साथ ही सभी 60 वार्डों से जीतकर आए पार्षदों ने भी शपथ लिया। प्रदेश के गृहमंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा की उपस्थिति में दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

आगामी पांच वर्ष तक अब दुर्ग शहर की सरकार की बागडोर अलका बाघमार के हाथो होगी। नगर निगम के चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद आज दुर्ग निगम के प्रांगण में शपथ समारोह का आयोजन किया गया। जिसमे प्रदेश के डिप्टी सीएम व गृहमंत्री विजय शर्मा बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनकी मौजूदगी में दुर्ग कलेक्टर ने नवनिर्वाचित अलका बाघमार को दुर्ग नगर निगम की महापौर के पद की शपथ दिलाई। इसके बाद चुनाव में विजयी सभी 60 पार्षदों को भी शपथ दिलाई गई।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने महापौर अलका बाघमार और सभी वार्डों के पार्षदों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा की दुर्ग शहर का अब तेज गति से विकास किया जा सकेगा। वहीं दुर्ग नगर निगम की महापौर अलका बाघमार ने कहा कि आने वाले दिनों में पानी की समस्या फिर से शुरू हो जायेगी। इसलिए दुर्ग शहर में पानी की समस्या और सफाई को लेकर उनकी पहली प्राथमिकता होगी।

जगदलपुर में महापौर और पार्षदों का शपथ

जगदलपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव की उपस्थिति में नगर पालिक निगम जगदलपुर के नव निर्वाचित महापौर एवं पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को बस्तर की आराध्य देवी मां दन्तेश्वरी मंदिर प्रांगण जगदलपुर में संपन्न हुआ। इस मौके पर कलेक्टर हरिस एस ने महापौर एवं

पार्षदों को शपथ दिलाई।

महापौर संजय पांडे ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव की उपस्थिति में शपथ ग्रहण किया, इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सभी नव-निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए विश्वास जताया कि नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदगण अटल विश्वास पत्र में किए गए प्रत्येक वादे को पूरा कर जगदलपुर शहर को स्वच्छ, सुन्दर एवं सुविधापूर्ण शहर बनाने की दिशा में दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार जगदलपुर शहर की तरक्की के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी। इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बीते 15 महीने में प्रदेश के नगरीय निकायों में 7500 करोड़ रुपये से अधिक राशि से विकास कार्य किया गया है। वहीं जगदलपुर शहर के लिए 82 करोड़ रुपए से अधिक लागत से आधारभूत संरचना विकसित किया जा रहा है। आगामी दिनों में जगदलपुर के 50 वर्षों की जरूरत को ध्यान रखकर शहर के समग्र विकास की दिशा में हम सभी मिलकर पहल करेंगे। इस दौरान सांसद बस्तर महेश कश्यप और विधायक जगदलपुर किरण देव ने भी सम्बोधित करते हुए जगदलपुर शहर के सर्वांगीण विकास हेतु हरसम्भव पहल करने का संकल्प व्यक्त किया। शपथ ग्रहण उपरांत महापौर संजय पांडे ने उप मुख्यमंत्री अरूण साव एवं विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। समारोह में विधायक चित्रकोट विनायक गोयल, विधायक केशकाल नीलकंठ टीकाम, विधायक दंतेवाड़ा चैतराम अटामी, बस्तर राज परिवार के कमलचन्द्र भंजदेव सहित अनेक जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। समारोह के अंत में महापौर संजय पांडे ने सभी अतिथियों, जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों का आभार व्यक्त किया।

धमतरी में महापौर रामू रोहरा ने ली शपथ

धमतरी नगर निगम चुनाव परिणाम आने के 8 दिन बाद शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन आज किया गया। महापौर रामू रोहरा सहित सभी 40 वार्ड पार्षदों ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ लिया। महापौर सहित सभी पार्षदों को धमतरी कलेक्टर नम्रता गांधी ने शपथ दिलाई।कार्यक्रम का आयोजन धमतरी के इंडोर स्टेडियम में रखा गया था।वही इस कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री टंक राम वर्मा, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, महासमुंद सांसद रूप कुमारी चौधरी, कुरूद विधायक अजय चंद्राकर एवं भाजपा के सभी नेता, कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।

शपथ ग्रहण के बाद महापौर रामू रोहरा ने नगर निगम पहुंचे विधि विधान से पूजा अर्चना कर नगर निगम कार्यालय के भीतर प्रवेश किया।जिसके बाद पदभार ग्रहण किया मीडिया से चर्चा के दौरान नव नियुक्त महापौर रामू रोहरा ने कहा कि उनका एक ही मुद्दा है शहर विकास का और शहर विकास को लेकर रणनीति बनाकर काम करेंगे।उन्होंने कहा कि शहर के सभी 40 वार्डों में बिना भेदभाव के विकास के कार्य किया जाएगा।वही प्रभारी मंत्री ने कहा कि अब चौपल इंजन की सरकार बन गई है,अब शहर से लेकर गांवों का सर्वांगीण विकास होगा।

40 साल बाद भोपालपटनम में होगा भाजपा का कब्जा, कांग्रेस को मिली करारी हार

बीजापुर। बीजापुर जिले के जनपद पंचायत भोपालपटनम के इतिहास में पहली बार भोपालपटनम जनपद पंचायत में भाजपा समर्थित जनप्रतिनिधियों का कब्ज़ा होगा। चार दशकों से भोपालपटनम जनपद पंचायत पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। 2025 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को करारी शिकस्त देकर कई वर्षो से संघर्ष करने के बाद भाजपा इस बार अपना परचम लहराया है। 40 वर्षों बाद जनपद की सत्ता पर काबिज होने भाजपाइयों में खुशी कि लहर हैं। इस बार भाजपा के कार्यकर्ताओ ने कड़ी मेहनत कर संगठन को मजबूत किया हैं। गावों में हर किसी से मिलकर उन्हें भरोसे में लेकर कार्यकर्तृता वोट बटोरने

में सफल हुए और इन्हे उन्हें बहुमत मिला। दिल्ली में 25 साल बाद भाजपा सरकार में आई हैं। इसी तरह चालीस साल बाद जनपदपंचायत भोपालपटनम में भाजपा के जनप्रतिनिधि चुने गये हैं। एक तरह से यह भी देखने को मिला हैं कि नक्सल दहशत कम होने के चलते इसका खासा प्रभाव भी पड़ा हैं। सरकार ने बड़ी एनकाउंटर कर नक्सलियों की कमर तोड़ी है। यह भी वजह है कि भाजपा के कार्यकर्ता निडर होकर हर गांव में घुसकर अपनी पार्टी का प्रचार किए हैं और इन्हे इसका फायदा भी मिला हैं। भोपालपटनम ब्लॉक में 10 जनपद पंचायतो की सीट पर 7 जनपद पंचायत कि सीट पर भाजपा समर्पित प्रत्याशी जीते हैं। कड़े मुकाबले में भाजपा प्रत्यशियों ने दिग्गजों को भी हराया है।

चुनाव संपन्न होने के बाद जीते हुए जनप्रतिनिधि और उनके समर्थक उन्हें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने की जोर लगा रहे हैं।लम्बे समय बाद जनपद में भाजपा के बहुमत के बाद पदों में बैठने राजधानी कि दौड़ लगा रहे हैं। चुनाव के वक्त चुनावी मैदान में भाजपा के उभरते चेहरे नजर आये हैं। जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया हैं।

अध्यक्ष के इन नाम पर चर्चा- गणेश पोट्टम, राहुल यालम, और सरिता कुड़ेम के नामों कि चर्चा हो रही हैं। सरिता कुड़ेम का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। क्योंकि उन्होंने वर्तमान जनपद अध्यक्ष निर्मला मरपल्ली व 20 सालों से सरपंच रही टिंगे चिन्नाबाई को हराया है। सरिता कुडेम बड़े नेताओं के संपर्क में भी हैं।

उपाध्यक्ष की दौड़ में- सबसे पहला नाम नीलम गनपत का है, वही रीना भगत और तनुजा कुमार का नाम भी आगे है। नीलम गणपत पिछले 35 सालों से भाजपा में सक्रिय रहकर काम कर रहे है, भाजपा मंडल अध्यक्ष सहित कई पदों में भी थे, भाजपा से समर्थन नही मिलने से निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत हासिल की। उनका नाम आगे हैं। वे भी भाजपा के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं।

लापता मां को ढूंढ निकाला

जाना था बेटी के घर, पर पहुंच गई वृद्ध आश्रम

कोरबा। रायगढ़ जिले के खरसिया क्षेत्र से लापता हुई एक बुजुर्ग महिला को उनके परिजनों ने आखिरकार खोज निकाला। महिला अपनी बेटी के पास जाने के लिए घर से निकली थी और इस दौरान वह कोरबा आ पहुंची जहां पर भटकते हुए वृद्ध आश्रम पहुंच गई थी। परिजन वृद्ध आश्रम से महिला को घर ले गए है।

जानकारी के मुताबिक, कोरबा में दो दशक से सर्वमंगला मंदिर के पास यह वृद्ध आश्रम है, जहां पर वर्तमान में 26 बुजर्ग महिला और पुरुष रह रहे हैं। इनमें उम्र दराज महिला और पुरुष शामिल हैं। इन्हीं के बीच 70 वर्षीय महिला मेंमबाई एक वर्ष से रह रही थी। एक साल पहले मेंमबाई अपनी बेटी के यहां जाने के लिए घर ट्रेन से निकली थी। इस दौरान वह कोरबा आ पहुंची जहां पर भटकते हुए वृद्ध आश्रम पहुंच गई।

वृद्ध आश्रम के केयरटेकर वीरू यादव ने बताया कि एक वर्ष पहले महिला का यहां पर

आना हुआ था। तब से उनकी देखभाल की जा रही थी। अब अनके परिजनों को जब इसकी जानकारी हुई वे इन्हें लेने के लिए वृद्ध आश्रम आए। मेंमबाई को उनके परिजनों के साथ भेज दिया गया है।

घर की महिला सदस्य के लापता होने से उनके परिजन परेशान थे और लगातार तलाश कर रहे थे। शिवनारायण ने बताया कि एक रिश्तेदार मां सर्वमंगला मंदिर दर्शन करने आया हुआ था उसकी नजर पड़ने पर उन्हें सूचना मिली थी कि उनकी मां कोरबा में इस स्थान पर है। मां के सुरक्षित मिलने से सब काफी खुश हैं और उन्हें घर ले आए हैं।

भाजपा पार्षद पर चाकू से हमला करने का असफल प्रयास

■ पार्षदों ने घेरा चिखली थाना

राजनांदगांव। चिखली शांतिनगर के भाजपा पार्षद सुनील साहू पर बीती रात को चाकू से हमला करने का असफल प्रयास किया गया। पार्षद पर हमले से गुस्साए पार्टी के साथी पार्षदों ने मोहल्लेवासियों के साथ शनिवार को चिखली पुलिस चौकी का घेराव कर दिया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई जिसमें पूर्व में आरोपियों के खिलाफ की गई शिकायत पर सख्तीपूर्वक कार्रवाई नहीं करने के लिए चिखली पुलिस चौकी प्रभारी और स्टाफ पर सांठगांठ का आरोप लगाया गया।

दरअसल, कांग्रेस के हारे प्रापाशी देवेश वैष्णव पर साथियों के साथ वार्ड का माहौल खराब करने का भी आरोप लगाया गया है। सुनील साहू हाल ही में भाजपा के पार्षद निर्वाचित हुए हैं। उनके प्रतिद्वंदी के तौर पर काग्रेस से देवेश वैष्णव ने मुकाबला किया था। वह लॉटरी पद्धति में आए नतीजे में हार गए तब से वह मोहल्ले में खुन्नस पालकर लोगों को डरा-धमका रहे हैं। भाजपा पार्षद सुनील साहू का आरोप है कि पिछले कुछ दिनों से वार्ड में अलग-अलग घटनाओं की पुलिस से आरोपियों के खिलाफ

शिकायत की गई है। एक अधिवक्ता के साथ भी मारपीट के मामले में की गई शिकायत को लेकर पुलिस ने उचित कार्रवाई नहीं की। ऐसे में देवेश वैष्णव के कथित रगदारी करने वाले युवकों ने उत्पात मचा रखा है।

पुलिस चौकी में धावा बोलने की खबर के बाद मुख्य प्रवेश द्वार की बंद कर दिया गया। भाजपा पार्षद के साथ चाकू से हमला करने के मामले को लेकर साथी पार्षदों ने गेट के सामने नारेबाजी की। बाद में पुलिस चौकी परिसर में घुसकर एसपी को मौके पर बुलाने की मांग करते हुए हंगामा किया गया।

सुकमा में नक्सलियों के साथ सुरक्षाबलों की मुठभेड़ में दो नक्सली ढेर

सुकमा। छत्तीसगढ़ में काफी समय से नक्सली फिर से एक्टिव हो गये हैं। सुरक्षाबलों की बड़े एक्शन के बाद अन्य नक्सली सुरक्षाबलों से बदला लेने के मूड में चल रहे हैं। काफी समय से मुठभेड़ की खबरें आ रही हैं। ताजा रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है जिसमें 2 नक्सली मारे गये हैं। पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के किस्टाराम थाना क्षेत्र में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है।

सुरक्षाबलों ने अभी तक दो नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि किस्टाराम क्षेत्र में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर शुक्रवार को सुकमा जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कोबरा बटालियन के संयुक्त दल को नक्सल विरोधी अभियान में रवाना किया गया था।

अधिकारियों ने बताया कि दल आज जब क्षेत्र में था तब नक्सलियों ने सुरक्षाबलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गयी। उन्होंने बताया कि आज सुबह से सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच रूक-रूक कर मुठभेड़ जारी है। अभी तक दो नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ स्थल और आस-पास के क्षेत्रों में सुरक्षा बलों ने खोजी अभियान शुरू किया है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

12वीं बोर्ड की परीक्षा शुरु, नहीं मिला कोई भी नकल प्रकरण

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 12वीं बोर्ड की परीक्षा के पहले दिन जिले में नकल का एक भी प्रकरण सामने नहीं आया। परीक्षा में नकल के विरूद्ध नकेल कसने के लिए शिक्षा विभाग ने तीन उडऩदस्ता दल का भी गठन किया है। हिन्दी विषय के साथ आज से शुरू हुई परीक्षा के लिए जिले में 88 से ज्यादा केंद्र बनाए गए हैं। तकरीबन 9 हजार से ज्यादा विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा केंद्रों में समय से पूर्व परीक्षार्थी पहुंच गए थे और प्रवेश से पहले परीक्षार्थियों को कड़ी जांच के बीच से गुजरना पड़ा। आज से शुरु हुई परीक्षा आगामी 28 मार्च तक चलेगा।

कलेक्टर ने किया परीक्षा केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी की मुख्य परीक्षा एवं हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा 1 मार्च से प्रारंभ हो गई है। 1 मार्च को हायर सेकेण्डरी की हिन्दी विषय की परीक्षा आयोजित की गई। कलेक्टर श्री दीपक कुमार अग्रवाल ने शनिवार को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोचवाय एवं सड़कपरसुली का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने यहां पर परीक्षा हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं और परीक्षार्थियों की उपस्थिति की जानकारी ली। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी श्री ए.के. सारस्वत भी मौजूद थे। हायर सेकेण्डरी की हिन्दी पाठ्यक्रम की परीक्षा में कोचवाय के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केन्द्र में 86 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। इसी प्रकार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सड़क परसुली परीक्षा केन्द्र में भी 49 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। कलेक्टर ने सभी परीक्षा केन्द्र प्रभारियों और अधिकारियों को निर्देश दिए कि बोर्ड परीक्षा के पेपर की गोपनीयता बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें।

दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनने की ओर गेवरा

कोरबा। भारत सरकार के कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल इंडिया लिमिटेड की मेगा परियोजना गेवरा खदान जल्द ही दुनिया के सबसे बड़ी ओपन कास्ट कोल माइंस बनने जा रही है। जिसे सालाना 70 मिलियन टन कोयला उत्पादन के लिए पर्यावरणीय मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद एसईसीएल प्रबंधन ने तेज गति से खदान के विस्तार की दिशा में काम शुरू कर दिया है। आसपास के 10 से ज्यादा गांव की जमीन अधिग्रहण कर अन्य प्रक्रियाओं को रिकॉर्ड समय में पूरा करना होगा। फिलहाल दुनिया की सबसे बड़ी ओपन कास्ट कोल माइंस संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्लैक थंडर माइंड को माना जाता है। लेकिन अब जल्द ही इस खदान से दुनिया के सबसे बड़े कोयला खदान होने का तमगा छिन जाएगा और यह रिकॉर्ड कोरबा जिले में स्थापित गेवरा कोल माइंस के नाम पर दर्ज हो जाएगा। गेवरा खदान से पहली बार वर्ष 1981 में कोयला खनन शुरू हुआ था। जी बीते 43 वर्ष से देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रही है।

युवक ने पड़ोसी के बछड़े की निर्मम हत्या की

दुर्ग। दुर्ग के भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र में घर में पड़ोसी के गाय का बछड़ा आने से नाराज होकर युवक ने उसकी निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को बोरी में भरकर नाले में फेंक दिया। इस मामले में पुलिस ने पड़ोसी संतू टंडन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सुपेला थाना प्रभारी राजेश मिश्रा ने बताया कि भारत माता चौक कृष्णानगर सुपेला निवासी प्रदीप कुमार (24 वर्ष) ने थाने में आकर शिकायत की। जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम,2004 की धारा 10, 325 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई थी।प्रदीप ने पुलिस को बताया कि वह अपने घर में गाय पालने का काम करता है। 25 फरवरी को उसकी गाय का बछड़ा गायब हो गया। इस पर उसने घर में लगे सीसीटीवी की जांच की। फुटेज देखने पर पता चला कि गाय का बछड़ा पड़ोस में रहने वाले संतू टंडन के घर चला गया था जो वापस नहीं आया। संतू साइकिल से बोरी मे बांधकर बछड़े को ले जाता दिखाई दिया।

बच्चे को लेकर सोने गई मां मच्छरदानी में घुसा नाग

कोरबा। कोरबा जिले में शुक्रवार की रात मानिकपुर के एक घर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक जहरीला नाग रात के समय मच्छरदानी में घुस आया। यह घटना तब सामने आई जब घर के सदस्य सोने की तैयारी कर रहे थे। माँ अपने बच्चों को लेकर बिस्तर पर पहुची ही थी कि सांप का अचानक मच्छरदानी के अंदर सांप का फुंकार सुनकर कमरे से चीखपुकार मचाते हुए कमरे से बाहर निकली और इसकी सूचना अन्य लोगो को दी जिसके बाद हड़कप मच गया सांप बिस्तर के अंदर फुंकार मारे फन फैलाया हुआ था। उन्होंने देखा कि एक 5 फिट बड़ा जहरीला नाग फूंकार मार रहा था जो कि उसमें फंसा हुआ था परिवार के सदस्यों ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय सर्प रेस्क्यू टीम को दी। कुछ ही देर में स्नेक रेस्क्यूर अतुल सोनी उमेश यादव मौके पर पहुंचे उन्होंने सावधानीपूर्वक सांप को बाहर निकाला। स्नैक कैचर उमेश यादव ने बताया कि मानिकपुर से फोन आया कि जवाहर खंडे के घर पर एक सांप फन फैलाए बिस्तर पर देखा गया है जहां मौके पर पहुंचे रेसक्यू किया गया।

पाली महोत्सव से कोरबा को मिल रही अलग पहचानः मंत्री देवांगन

कोरबा। प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग व श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन के मुख्य आतिथ्य में महाशिवरात्रि पर्व पर पाली में आयोजित दो दिवसीय पाली महोत्सव का समापन समारोह आयोजित हुआ। कैबिनेट मंत्री श्री देवांगन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पाली महोत्सव कोरबा वासियो के लिए गौरव की बात है। उन्होंने क्षेत्रवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पाली देवाधिदेव भगवान शिव व महिषासुर मर्दिनी की नगरी है। जिसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। तीज, त्यौहार, मड़ई, मेला, सुआ, ददरिया ये हमारी संस्कृति की पहचान है, इसकी रक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी है।

कैबिनट मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि पाली महोत्सव के दो दिवसीय कार्यक्रम में बॉलीवुड, छालीवुड सहित स्थानीय कलाकारों द्वारा अपनी कला संस्कृति का शानदार प्रस्तुति दी। जिसका हम सभी ने भरपूर आनंद लिया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य स्थानीय कला संस्कृति को

बढ़ावा देना, स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान करना एवं मंच के माध्यम से आमजनों का मनोरंजन करना है। जिला प्रशासन द्वारा महोत्सव का बहुत अच्छा आयोजन किया गया है। आगे भी प्रशासन द्वारा इस प्रकार का आयोजन किया जाता रहेगा। कैबिनेट मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि प्रदेश सरकार के गठन के साथ ही मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के कुशल नेतृत्व में प्रदेश का विकास तेजी से किया जा रहा है। अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आमजन लाभान्वित हो रहे हैं। किसानों के परिश्रम को सम्मान देते हुए उनके उपज को 3100 रुपए प्रति क्विंटल एवं 21 क्विन्टल प्रति एकड़ की दर से खरीदी की गई है। इसी प्रकार प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में आगे भी निरंतर कार्य किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पाली में भी क्षेत्रवासियों की मांग को ध्यान में रखकर अनेक विकास कार्यो की स्वीकृति प्रदान की गई है। यहां के प्रमुख धार्मिक व पर्यटन स्थल की व्यवस्थित विकास हेतु कार्य योजना तैयार कर डीएमएफ के आने वाली बैठक में अनुमोदन कर कार्य की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार आगे भी विकास कार्य निरंतर जारी रहेगा। श्री देवांगन ने गरिमामय कार्यक्रम के आयोजन के लिए जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया।

समापन समरोह को सम्बोधित करते हुए कलेक्टर श्री वसंत ने सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पाली की शिव मंदिर की गरिमा को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्षेत्र के विकास के सम्बंध में आने वाली बैठक में चर्चा कर ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का व्यवस्थित ढंग से विकास किया जाएगा। जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के आपसी समन्वय से विकास कार्यो में तेजी आएगी । आभार प्रदर्शन जिला पंचायत सीईओ श्री दिनेश नाग ने किया।

समारोह को विधायक पाली तानाखार श्री तुलेश्वर मरकाम, विधायक कटघोरा श्री प्रेमचंद पटेल,नवनिर्वाचित महापौर कोरबा श्रीमती संजू देवी राजपूत सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने सम्बोधित किया एवं सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम का आनंद लेने का आग्रह किया। इस दौरान जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पाली महोत्सव के अंतर्गत आयोजित विडियोग्राफी प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। जिसके अंतर्गत प्रथम पुरस्कार पाली के रितिक कुमार पटेल, द्वितीय स्थान आईटीआई रामपुर कोरबा के विवेक कुमार यादव , तृतीय स्थान पाली के किसन कुमार मरकाम ने प्राप्त किया। सभी विजेताओं को मंच से अतिथियो द्वारा सम्मानित किया गया।

कांकेर में पूर्व सरपंच सहित 18 लोग गिरफ्तार

कांकेर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में ग्राम पंचायत पुसवाड़ा में हिंसा हुई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। 15 आरोपियों की गिरफ्तारी से पहले कांकेर पुलिस ने पूर्व सरपंच सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अबतक कुल 18 लोगों को हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। कांकेर पुलिस ने पुसवाड़ा हिंसा केस में सरपंच प्रत्याशी समेत 50 से अधिक लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है। जो आरोपी फरार हैं उनकी तलाश भी जारी है।

कांकेर पुलिस का कहना है कि 17 फरवरी को मतदान के बाद वोटों की गिनती हुई। वोटों की गिनती में एक सरपंच प्रत्याशी की हार हुई। आरोप है कि पराजित प्रत्याशी रुकमणी कोसम और उसके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। पराजित प्रत्याशी और उसके समर्थकों का कहना था कि मतगणना में गड़बड़ी की गई है। आरोपियों ने मतदान दल को ही केंद्र के भीतर बंद कर दिया। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो उसके साथ भी मारपीट की गई। पुलिस और मतदान दल की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। आरोप है कि मतपेटी लूटने की भी कोशिश की गई। करीब 4 घंटों तक हंगामा चलता रहा। बड़ी मुश्किल से मतदान दल और मतपेटियों को वहां से बाहर निकाला जा सका। हमले में पुलिस के 8 जवान जख्मी हुए थे। मतदान केंद्र के रिटर्निंग आफिसर अशोक गोटे चारामा ने पुलिस में इस संबंध में अपराध दर्ज कराया था।

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल को जन्मदिन पर सीएम साय ने दी बधाई, उत्तम स्वास्थ्य की कामना की

रायपुर। छत्तीसगढ़ के दसवें राज्यपाल रमेन डेका के जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उत्तम स्वास्थ्य एवं सुखमय जीवन की कामना की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका, आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. राज्यपाल के रूप में आपके मार्गदर्शन में हमारी सरकार संवैधानिक मूल्यों को आत्मसात करते हुए प्रदेश के लोगों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मां कामाख्या से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं सुखमय जीवन की कामना करता हूं। बता दें कि छत्तीसगढ़ के 10 वें राज्यपाल रमेन डेका का जन्म 1 मार्च 1954 को असम के सुआलकुची, कामरूप (असम) में हुआ था। उनके परिवार में धर्म पत्नी रानी डेका काकोटी एवं दो बच्चे हैं। उन्होंने बीए की डिग्री दर्शनशास्त्र और अर्थशास्त्र विषय में प्राग्ज्योतिष कॉलेज, गुवाहाटी विश्वविद्यालय असम से प्राप्त की। सन् 1977 से राजनीति में सक्रिय रमेन डेका वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। रमेन डेका वर्ष 2006 में असम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं. वे 2021 अगस्त माह से असम राज्य के नवाचार एवं रूपान्तरण आयोग के (कैबिनेट मंत्री का दर्जा) के उपाध्यक्ष पद पर 29 जुलाई 2024 तक रहे है। वे दो बार सांसद रहे। पहली बार वर्ष 2009 में 15वीं लोकसभा के लिए असम के मंगलदोई सीट से सांसद चुने गये थे।

निकाय और त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव के बाद कांग्रेस ने की पर्यवेक्षकों की नियुक्ति

रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने शनिवार को नगर निगमों में सभापति और नेताप्रतिपक्ष और जिला पंचायत में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। पर्यवेक्षकों की सूची में अनुभवी नेताओं के साथ महिला प्रतिनिधियों के भी नाम शामिल है। प्रतिमा चंद्राकर को रायपुर नगर निगम, प्रमोद दुबे को बिलासपुर नगर निगम और शिव डहरिया को रायगढ़ नगर निगम में नेताप्रतिपक्ष चयन की जिम्मेदारी दी गई है। जयसिंह अग्रवाल को मनेंद्रगढ़ की तो जांजगीर-चांपा जिला पंचायत की जिम्मेदारी सांसद ज्योत्सना महंत को सौंपी गई है। पर्यवेक्षक नियुक्ति को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि जिला पंचायतों में कांग्रेस अच्छी स्थिति में है। इसलिए सभी जिलों के जिला पंचायतों के अध्यक्षों के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक और प्रभारी की नियुक्ति किए गए हैं। नगर निगम और नगर पंचायत में सभापति, नेताप्रतिपक्ष चयन के लिए भी नियुक्ती की गई है। प्रभारी-पर्यवेक्षक जल्द से जल्द अपने-अपने क्षेत्र में बैठक कर ज्यादा से ज्यादा अध्यक्ष चुनकर आए ये सुनिश्चित करेंगे।

कभी कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ूंगा : अमरजीत भगत

रायपुर। पूर्व खाद्य मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमरजीत भगत ने लल्लूराम डॉट कॉम से खास बातचीत में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, सरगुजा में सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के सीतापुर नगर पंचायत में कांग्रेस को जीत दिलाई। लोकसभा चुनाव में भी सीतापुर विधानसभा से मैं कांग्रेस को लीड दिलाया। बस्तर व सरगुजा के साथ जो चलेगा उसकी सरकार बनेगी। अमरजीत ने कहा, जब से देश आजाद हुआ है तब से आज तक सरगुजा से किसी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बागडोर नहीं संभाली है। मैं कभी कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा, कांग्रेस का झंडा थामे रहूंगा। वह पार्टी के छोटे सिपाही हैं, जो हाई कमान का आदेश होता है वह उसका पालन करते हैं।

सेवानिवृत होने पर कलेक्टर ने कर्मचारियों को दी भावभीनी विदाई

रायपुर। कलेक्टर बंगले में शुक्रवार की शाम बड़ा अच्छा आयोजन हुआ। जिसमें कलेक्टर डॉ गौरव सिंह और उनकी पत्नी श्रीमती सुनीता सिंह ने 30 वर्षों से सेवा देने वाले नगर सेना नगर सैनिक श्री भुरूलाल बरिहा को सेवानिवृत होने पर शॉल तथा श्रीफल देकर भावभीनी विदाई दी। उन्होंने श्री बरिहा की स्वस्थ्य रहने और सुदीर्घ जीवन की कामना की। इसी प्रकार कलेक्टर डॉ सिंह ने कलेक्टर कार्यालय राजस्व शाखा में सहायक वर्ग-2 के पद पर कार्यरत श्रीमती उषा दरवलकर के सेवानिवृत्त होने पर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित विदाई समारोह में शॉल, पुष्पगुच्छ तथा श्रीफल भेंट कर भावभीनी विदाई दी। इस मौके पर कलेक्टर डॉ सिंह ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनकी कार्य प्रणाली की सराहना करते हुए उनके उज्जवल एवं सुखद भविष्य की कामना की। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्रीमती निधि साहू, श्री नवीन कुमार ठाकुर, श्रीमती अभिलाषा पैकरा, डिप्टी कलेक्टर श्री उत्तम रजक तथा स्टेनो टू कलेक्टर श्री मुक्तेश्वर पटेल सहित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

श्रीराम कथा ज्ञान यज्ञ 7 से 9 मार्च तक

रायपुर। युगतुलसी श्री रामकिंकर जी महाराज की हृदयात्मजा कथा व्यास दीदी मां मंदाकिनी की श्रीमुख से श्रीराम कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन 7 से 9 मार्च 2025 को सिंधु पैलेस शंकरनगर, बीटीआई मैदान के सामने किया गया है। श्रीरामकिंकर आध्यात्मिक मिशन की ओर से बताया गया है कि कथा प्रति दिन शाम को शाम 6.30 से 8.30 बजे तक होगा। इससे पूर्व शाम को 5.30 से 6.30 बजे तक भक्ति संगीत होगी।

उप मुख्यमंत्री साव ने नगरीय निकायों के कार्यों की समीक्षा की

रायपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ सभी नगरीय निकायों की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक में सभी नगरीय निकायों को केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 में अच्छी रैंकिंग हासिल करने के लिए पुख्ता तैयारी के निर्देश दिए। आगामी मार्च महीने के प्रथम सप्ताह में सर्वेक्षण दलों द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण-2024, ओडीएफ एवं जीएफसी प्रमाणीकरण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने ने बैठक में सर्वेक्षण के दौरान मूल्यांकन के लिए प्रमुख दस मापदण्डों, 54 प्रमुख संकेतको एवं 166 सह-संकेतकों की जानकारी देते हुए सभी बिन्दुओं पर निकायों को वांछित तैयारियां रखने को कहा। इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इस संबंध में निकायों द्वारा अब तक की गई तैयारियों और व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली।

डिप्टी सीएम साव ने नगरीय क्षेत्रों में दर्शनीय स्वच्छता के लिए सार्वजनिक व व्यावसायिक क्षेत्रों में नियमित सफाई, ट्विन-बिन्स की उपलब्धता, शत-प्रतिशत ठोस अपशिष्ट संग्रहण एवं परिवहन, सीटीयू/ब्लैक स्पॉट/जीवीपी से मुक्त शहर, बैक-लेन/नालियों एवं जल-स्त्रोतों की साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी समीक्षा बैठकों में सभी नगरीय निकायों के स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 के परिणामों की निकायवार समीक्षा करने की बात कही। निकायों के प्रदर्शन एवं रैंकिंग के विश्लेषण के बाद इसमें गिरावट पाए जाने पर राज्य शासन स्तर द्वारा कार्यवाही की जाएगी।

उप मुख्यमंत्री साव ने बैठक में निकायों में लंबित विद्युत देयकों के निपटान एवं 15वें वित्त आयोग से संबंधित कार्यवाहियां समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी नगरीय निकायों को 15 दिनों में विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप सिटी डेव्हलपमेंट प्लान तैयार कर संचालनालय भेजने को कहा।

छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित समिति कक्ष में आयोजित बैठक में सभी नगर निगमों के आयुक्त तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्चुअली शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री साव के साथ नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. और संचालक आर. एक्का भी बैठक में मौजूद थे। सुडा (स्था) के सीईओ शशांक पाण्डेय और नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक पुलक भट्टाचार्य भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उद्योगपतियों को प्रदेश में निवेश के लिए किया आमंत्रित

कहा- नई उद्योग नीति जारी किए हैं, देश में हो रही है सराहना

रायपुर। छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग कार्यक्रम मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उद्यमियों को छत्तीसगढ़ में आमंत्रित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ लगातार विकास कर रहा है। प्रदेश में उद्योग को बढ़ाने वातावरण उचित है। नई उद्योग नीति जारी किए हैं। बड़ी मेहनत के साथ उद्योग नीति को तैयार किए हैं, जिसकी पूरे देश में सराहना हो रही है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम के दौरान प्रदेश में निवेश करने वाले 14 उद्योगपतियों को प्रमाण पत्र दिया। ईडीआईआई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बांटे और एमएसएमई उद्योगपति को सहायता राशि भी दी गई है। इसके अलावा नए उद्योग लगाने वाले निवेशकों को इनविटेशन लेटर भी दिया गया।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प रखा है। उद्योगों को बढ़ावा देने हमने योजनाएं तैयार की हैं। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। हम इस योजना में काम करने जा रहे हैं। हम छोटा पौधा लगाते हैं, आगे चलकर यह विशाल वृक्ष बनता है, जिसे बढ़ाने हम दृढ़ संकल्पित हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रदेश में इंडस्ट्रियल पार्क भी बना रहे हैं। नई दिल्ली और मुंबई में इन्वेस्टर समिट कर चुके हैं। हमें 1 लाख करोड़ के प्रस्ताव भी मिले हैं। ज्यादा से ज्यादा काम मिले, इसके लिए हम काम कर रहे हैं।

कार्यक्रम में मौजूद वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने उद्योग को पूरी तरह से बैठा दिया था। प्रदेश के विकास में एक बड़ा गड्ढा हो गया था। आज भाजपा सरकार उसी को भरने की कोशिश कर रही है। हमारी सरकार ने नई उद्योग नीति बनाई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे। पहले से चल रहे उद्योगों को लाभ मिल सके।

मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्योगों का साथ चाहिए। रैंप (Rising and Accelerating MSME Performance) योजना का शुभारंभ किया गया है। भारत सरकार की योजना की छत्तीसगढ़ में भी शुरुआत की गई है।

रणनीति तय करने जय व्यापार पैनल की हुई बैठक

रायपुर। जय व्यापार पैनल की ओर से श्री जितेन्द्र दोशी एवं श्री विक्रम सिंहदेव ने बताया कि जय व्यापार पैनल के संरक्षक श्री महेन्द्र धाडीवाल के निवास पर जय व्यापार पैनल संरक्षक मंडल एवं पदाधिकारियों की बैठक हुई। जिसमें छत्तीसगढ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्ड्स्ट्रीज के होनें वाले आगामी चुनाव हेतु रणनीतियों पर हुई चर्चा। इस अवसर पर जय व्यापार पैनल ने आगामी चुनावों की तैयारियों पर भी चर्चा की। जय व्यापार पैनल व्यापारियों की आवाज को सशक्त करने और व्यापारिक समुदाय को एकजुट करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश के प्रत्येक व्यापारी तक जय व्यापार पैनल ने संगठन की विचारधारा और उद्देश्यों को पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाने की रूपरेखा भी तैयार की गई। जय व्यापार पैनल ने संगठन के उद्देश्यों और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला गया।

बैठक में आसुदामल वाधवानी , महेंद्र कुमार धाडीवाल , हनुमान प्रसाद अग्रवाल, रामजी पटेल, यू.एन. अग्रवाल, अमर पारवानी , अजय भसीन, उत्तम गोलछा, मगेलाल मालू, जितेन्द्र दोशी , संजय गंगवाल, राजेन्द्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, मनमोहन अग्रवाल, परमानन्द जैन, राम मंधान, सुरिंदर सिंह, भरत जैन, भरत बजाज एवं नरेन्द्र दुग्गड व अन्य मौजूद थे।

जय व्यापार पैनल ने मनमोहन अग्रवाल को मुख्य चुनाव संचालक बनाया

जय व्यापार पैनल की ओर से श्री जितेन्द्र दोशी एवं श्री विक्रम सिंहदेव ने बताया कि छत्तीसगढ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्ड्स्ट्रीज 2025 के चुनाव हेतु जय व्यापार पैनल ने मुख्य चुनाव संचालक श्री मनमोहन अग्रवाल को नियुक्त किया है। साथ ही श्री नरेन्द्र दुग्गड ,श्री गार्गीशंकर मिश्रा, कैलाश खेमानी,विनय बजाज को चुनाव सह संचालक बनाया गया है। जय व्यापार पैनल ने मुख्य चुनाव अधिकारी श्री शिवराज भंसाली को पत्र जारी कर इसकी जानकारी दे दी है।

सिलेबस में जो पढ़ा था वही आया पर्चे में, 12वीं हिन्दी का पेपर अच्छा बना

रायपुर। माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12 वीं की शिक्षा सत्र 24-25 के लिए हिन्दी के पर्चे के साथ शनिवार से परीक्षाएं शुरु हो गई। पहले दिन सरल पेपर से विद्यार्थियों के चेहरों में खुशी दिखी और उनका कहना था कि जो सिलेबस में था और जो पढ़े थे उसी में से प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए पेपर अच्छा बना।

राजधानी रायपुर के एक केंद्र में बच्चों का तिलक लगाकर परीक्षा केंद्र में स्वागत किया गया। वही मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने से मनाही को देखते हुए गेट पर छात्र छात्राओं की तलाशी भी ली गई। वहीं माशिमं सचिव की टीम और अन्य उडनदस्तों ने पहले ही दिन से परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया।

पहले दिन माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हिंदी विषय का पर्चा विद्यार्थियों से हल कराया। सुबह 9 बजे से शुरू हुई परीक्षा 12-15 बजे खत्म हुई जिसके बाद परीक्षा के केंद्रों से बाहर निकालने के बाद विद्यार्थियों ने बताया कि प्रश्नपत्र काफी सरल था लेकिन परीक्षा के सवाल काफी अधिक लंबे थे जिसके कारण समय की कमी परीक्षा में उन्हें देखने को मिली लेकिन अब प्रश्न पत्र हल करने के बाद में उम्मीद है कि जितनी तैयारी उन्होंने की थी उसके अनुरूप ही उन्हें अंक प्राप्त होंगे।

शौर्य भट्टाचार्य हासिल किया एसईसीएल छग ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब

रायपुर। एसईसीएल छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब दिल्ली के शौर्य भट्टाचार्य ने 249 के स्कोर के साथ एक करोड़ रुपये की इनामी राशि अपने नाम किया। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने शौर्य का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें जीत की बधाई दी और इनामी राशि का चेक प्रदान

किया। इस अवसर पर पीजीटीआई के प्रेसिडेंट कपिल देव, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल), बिलासपुर के डायरेक्टर (पर्सनल) बिरांची दास उपस्थित थे। शौर्य भट्टाचार्य (64-61-61-63), जो रात भर पांच शॉट से आगे चल रहे थे, ने शुक्रवार को बढ़त हासिल करते हुए अपनी दूसरी पेशेवर जीत दर्ज की। 22 वर्षीय शौर्य, जो 2024 में पीजीटीआई इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर थे, ने टूर्नामेंट के दौरान सिर्फ एक बोगी गिराई। भट्टाचार्य ने 15 लाख रुपये का विजयी चेक प्राप्त किया, जिससे वे टाटा स्टील पीजीटीआई रैंकिंग में 59वें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गए। दिल्ली के सचिन बैसोया (67-62-64-61) ने पिछले दिन का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 61 बनाया और पांच स्थान ऊपर चढ़कर 22 अंडर 254 के स्कोर के साथ पार-69 कोर्स पर उपविजेता स्थान प्राप्त किया। श्रीलंका के एन. थंगाराजा (66-63-62-64) ने चौथे राउंड में 64 का स्कोर बनाकर 21 अंडर 255 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। सचिन बैसोया ने चौथे राउंड में एक ईगल, सात बर्डी और एक बोगी लगाकर सप्ताह का अंत उपविजेता के रूप में किया। सचिन को मिले 10 लाख रुपये के रनर-अप चेक ने उन्हें टाटा स्टील पीजीटीआई रैंकिंग में 20वें स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंचने में मदद की।

कांग्रेसियों ने ईडी के खिलाफ प्रदेशभर में किया प्रदर्शन

- जलाया ईडी और भाजपा का पुतला, कहा - हम डरने वाले नहीं

रायपुर। प्रदेशभर में शनिवार को ईडी के खिलाफ कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। बलौदाबाजार में जिला कांग्रेस अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर के नेतृत्व में शनिवार को गार्डन चौक में कांग्रेसियों ने भाजपा व ईडी का पुतला दहन कर ईडी की कार्रवाई का विरोध किया।

कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता शैलेष नितिन त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के लोगों को भाजपा डराना चाहती है पर हम डरने वाले लोगों में से नहीं है। अभी भाजपा बस्तर में लोहा निकालने फैक्ट्री लगवाने जा रही है, जिसका विरोध कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कवासी लखमा, दीपक बैज सहित अन्य नेताओं ने किया तो भाजपा ने ईडी का सहारा लेकर लखमा को जेल भिजवा दिया। वहीं दीपक बैज के घर का पुलिस रेकी कर रही है, जो कही न कहीं बस्तर की आवाज को दबाने का प्रयास है।

शैलेष नितिन ने कहा, कांग्रेस डरेगी नहीं, बस्तर वासियों के हित में हमेशा लड़ेगी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष हितेन्द्र ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस जब-जब भाजपा के भ्रष्टाचार व आम जनता के प्रति हो रहे अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाती है भाजपा डर जाती है और ईडी का सहारा लेकर डराने का प्रयास करती है। हम डरेंगे नहीं बल्कि और बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन होगा। तीन मार्च को रायपुर में बड़ा प्रदर्शन होगा, जिसमें हजारों की संख्या में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले से कांग्रेस कार्यकर्ता जाएंगे। प्रदर्शन में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रूपेश ठाकुर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

कांग्रेस के पास हार छिपाने का कोई बहाना नहीं, इसीलिए ईडी के नाम पर कर रहे झूठी राजनीति : साव

ईडी की जांच कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन तक पहुंचने के बाद सियासत गर्म है। कांग्रेस ने सरकार पर ईडी का दुरूपयोग कर डराने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जिस प्रकार से निकाय का परिणाम आया है, उसमें कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ है। कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा हुई है। कांग्रेस ईवीएम में भी पराजित हुई और मत पत्र में भी पराजित हुई । अब हार को छिपाने का कोई बहाना नहीं बचा है, इसलिए श्वष्ठ के नाम पर जनता में भ्रम फैलाने राजनीति कर रहे हैं। ईडी साक्ष्य और तथ्यों पर आधारित कार्रवाई कर रही है।

पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत पर निष्कासन कार्रवाई की चर्चा है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि अभी तो ये शुरुआत है, आगे देखिए और क्या होने वाला है।

वहीं उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने महापौर मीनल चौबे के बेटे का सड़क पर केक काटने के वायरल वीडियो पर कहा कि इस घटना की मुझे जानकारी नहीं है। इस पर संज्ञान जरूर लेंगे।

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने 3 मार्च को पेश होने वाले को लेकर कहा कि छग का रजत जयंती वर्ष हैं। विकसित छग 2047 को अचीव करने वाला ये बजट होगा। हमारा मूल मंत्र हैं सबका साथ सबका विकास। इसी पर हमारा फोकस है। हर वर्ग के विकास वाला ये बजट होगा।

छत्तीसगढ़ में पदोन्नति में आरक्षण बहाल, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया अंतरिम आदेश

रायपुर। शुक्रवार की देर शाम को सुप्रीम कोर्ट से उनके द्वारा लगाई याचिका पर फैसला हुआ जिसमें न्यायाधीश महोदय ने संगत मानते हुए पदोन्नति में आरक्षण को अंतिम आदेश के अध्ययधीन मानते हुए अनुमति दे दी है। उल्लेखनीय है कि विद्युत कंपनी में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों ने शुक्रवार की शाम को डंगनिया मुख्यालय के गेट के सामने बैठकर पदोन्नति में आरक्षण एवं अन्य सांगठनिक मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया।

कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष इं. आर. एल. ध्रुव बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग

अधिकारी कर्मचारी संघ द्वारा पदोन्नति में आरक्षण को लेकर माननीय हाई कोर्ट में याचिका क्र. 9778/2019 एवं अन्य प्रकरण में दिनांक 16.04.2024 को पारित आदेश को माननीय सुप्रीम कोर्ट में डायरी क्र. 5555/2025 द्वारा चुनौती दी गई, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 24.02.2025 की सुनवाई में पूर्व में जारी अंतरिम आदेश दिनांक - 01.05. 2023 के संगत मानते हुए पदोन्नति में आरक्षण को अंतिम आदेश के अध्ययधीन मानते हुए अनुमति दे दी है।

वकील की सुनवाई के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता की सुनवाई की गई। विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति प्रदान की जाती है। विलम्ब की क्षमा मांगने वाले आवेदन पर नोटिस जारी किया जाए साथ ही विशेष अनुमति याचिका पर भी।

डायरी संख्या 5555/2025 के तहत विशेष अनुमति याचिका के निपटारे तक एसएलपी (सी) संख्या 19668/2022 के समान निर्देश होंगे, ताकि राज्य को चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और नियुक्तियां और पदोन्नति करने की अनुमति दी जा सके, हालांकि, वे इन याचिकाओं के परिणाम के अधीन होंगे। सभी नियुक्ति और पदोन्नति आदेशों में विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि ऐसी नियुक्तियां और पदोन्नति वर्तमान कार्यवाही के अंतिम परिणाम के अधीन हैं। इस मामले को एसएलपी (सी) संख्या 18816-18817/2022 के साथ सूचीबद्ध करें।

कार्यालय, कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बालोद
Phone No. :- 07749-222370, Email Id : ee-res.balod@gov.in

मैनुअल पद्धति निविदा सूचना द्वितीय बार

क्रमांक / 18 / व.ले.लि./ग्रा.यां. सेवा / 2024-25 बालोद, दिनांक 28.02.2025

छत्तीसगढ के राज्यपाल की ओर से बालोद जिले में स्वीकृत निम्नलिखित कार्यों के लिये सामग्री प्रदाय हेतु लोक निर्माण विभाग में एकीकृत पंजीयन प्रणाली के तहत पंजीकृत ठेकेदार अथवा वाणिज्यिकर विभाग में सामग्री प्रदाय हेतु पंजीकृत फर्म / डीलर से कार्य विभाग मैन्युअल के अपेडिक्स 2.15 के अनुसार प्रपत्र 'सी' में स्पीड पोष्ट अथवा पंजीकृत डाक द्वारा तीन लिफाफा पद्धति में दिनांक 11.03.2025 को अपरान्ह 5.30 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाएँ दिनांक 12.03.2025 को प्रातः 11.30 बजे उपस्थित निविदाकारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी।

कार्य का नामः-

1. समुदाय के लिये सी.सी.चेक डेम सह पुलिया निर्माण कार्य ग्राम सुकड़ीगुहान ग्राम पंचायत सिंघोला विकासखण्ड डौण्डी जिला बालोद सामग्री प्रदाय की अनु. लागत राशि रू. 29.52 लाख अमानत राशि 22150/- निविदा प्रपत्र का मुल्य 1500/- सामग्री प्रदाय की अवधि 06 माह

निविदा दस्तावेज कार्यालय द्वारा विक्रय नहीं किया जावेगा, ऑनलाईन पोर्टल http://cg.nic.in/resworks/Tender test report.aspx या अन्य पोर्टल जिसे निविदा विज्ञप्ति में दर्शाया गया है दिनांक 28.02.2025 से डाउनलोड किया जा सकता है एवं कार्यालयीन अवधि में कार्यालय में उपस्थित होकर देखी जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग
बालोद जिला-बालोद (छ.ग.)

जी-242505639/3

राजनीति में स्वच्छ लोगों से मजबूत होगा भारत का लोकतंत्र

श्वेत मलिक

राजनीति में अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए। समाज को दिशा मिलेगी। स्वच्छ व साफ-सुथरी राजनीति होगी तो इससे बड़ा बदलाव होगा। नगर निगम से लेकर विधानसभा और संसद में जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनकी बात रखने और निराकरण करने में उनका नजरिया व महाअभियान जरूर बहुत बड़े परिणाम सामने लाएगा। डाक्टर, वकील, शिक्षक, कारोबारी, इंजीनियर व अन्य इससे प्रेरित होकर आगे आएंगे। स्वच्छ और उद्देश्यपूर्ण राजनीति को बड़ा बल मिलेगा। शिक्षित लोगों की राजनीति में भागीदारी बढने से समाज का भला होगा। इस तरह के प्रयास होना बहुत जरूरी है। अच्छे लोगों की आवश्यकता सामाजिक जीवन में हमेशा बनी रहती है। जब अच्छे लोग ज्यादा संख्या में किसी भी क्षेत्र में आएंगे तो गलत प्रवृत्ति वाले लोग निरुत्साहित होंगे। समाज में आज भी 95 फीसदी लोग अच्छे हैं लेकिन वे आवाज नहीं उठाते जबकि 5 प्रतिशत ही बुरे लोग हल्ला करते हैं। अच्छे लोग मिलकर राजनीति को और अच्छी तरह से बनाएं, इसलिए गुणवान लोगों और विद्वान लोगों को आगे आना चाहिए। देश की राजनीति को स्वच्छ और साफ-सुथरा बनाने के लिए युवाओं को आगे आने की जरूरत है। राजनीति के जरिए ही देश और समाज का विकास संभव है। वर्तमान में युवा केवल सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, जबकि उन्हें जमीन पर उतर कर कार्य करना चाहिए। आने वाला भविष्य युवाओं का है। आप 18 साल के हो चुके हैं, आपके पास अब लोकतंत्र की असीम ताकत है जिसका नाम वोट है। आप एक वोट से किसी की तकदीर बना और बिगाड़ सकते हैं। राजनीति में ऐसे कई युवाओं ने अपनी राय रखी कि चुनाव के समय राजनीतिक दल और प्रत्याशी थोड़ा लालच देकर 5 साल के लिए जाकर जम जाता है, फिर उसे कोई मतलब नहीं रहता है। राजनीति की वर्तमान में परिभाषा बदल गई है। अब राजा का बेटा राजा नहीं है, अब प्रजातंत्र में आमजन अहम हैं। लेकिन इसके लिए वोटरों को जागरूक होने की जरूरत है। बिना जागरूकता के बदलाव की उम्मीद करना बेमानी होगा। तस्वीर बदलनी है तो सभी को लोकतंत्र के यज्ञ में आहूति देने हेतु आगे आना होगा। यह सच है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति, राजनीति के प्रभाव से वंचित नहीं रह सकता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र की जीवंतता इस बात से तय होती है कि शासन-प्रशासन द्वारा सामाजिक-आर्थिक न्याय को अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक कितनी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। यह पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी का स्वप्न था और यहीं पर राजनीति की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। आज भी देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है और अभी भी इन गांवों में विकास का स्तर शहरों की अपेक्षा बराबर करना है। गांवों की अधिकांश जनसंख्या या तो निरक्षर या नाममात्र साक्षर होती है। सरकार के अनेक प्रयासों के बावजूद अभी भी गांवों में पूर्ण रूप से शिक्षित जनसंख्या कम है। ऐसी स्थिति में ही यदि राजनीति कुछ ऐसे गलत हाथों में चली जाती है जो अशिक्षित और कम जानकारी वाले लोगों का फायदा उठाते हैं तो समाज के साथ अनेक प्रकार का अन्याय होने लगता है। क्योंकि शासन प्रणाली से संबंधित जिन नीतियों को जन-उपयोगी बनाकर लागू किया जाता है वे भ्रष्टाचार के चलते अपने वांछित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बना कर देश की जनता ने भ्रष्टाचार खत्म करने पर सहमति प्रकट की। एक युगद्रष्टा एवं क्रांतिकारी समाज सुधारक के रूप में बाबा साहेब डा. भीम राव आम्बेडकर जैसे उच्चकोटि के विद्वानों, महापुरुषों एवं नीति-निर्माताओं ने जिन संकल्पों के साथ हमें हमारा संविधान दिया, उसमें समस्त राजनीति ने एक संरक्षक की भांति अपनी भूमिका निभाई। लेकिन कालांतर में राजनीति पर गलत दृष्टि डालने वालों ने जनप्रतिनिधि का मुखौटा लगाकर राजनीति का नायकत्व मतदाता से राजनेता की ओर स्थानांतरित कर दिया और इसी कारण राजनीति में अनेक प्रकार की विसंगतियां पैदा होने लगीं। राजनीति को स्वच्छ बनाने के लिए अच्छे नागरिकों को राजनीति में भाग लेना चाहिए व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वप्न 2047 में विकसित व आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए एकजुट होकर भारत को दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था, विश्वगुरु, विश्वशक्ति व एक बार फिर सोने की चिड़िया बनाएं।

दिल्ली को विश्वस्तरीय राजधानी बनाने का उचित अवसर

दीपक कुमार त्यागी

देश का दिल दिल्ली की पहचान दुनिया भर में भारत की राजधानी के रूप में होती है, जो एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में चलती है, जहां पर कुछ शक्तियां राज्य सरकार व कुछ शक्तियां केंद्र की सरकार के पास होती है। केंद्र व राज्य दोनों के बेहतर सामंजस्य से ही दिल्ली का शासन बेहतर ढंग से चल सकता है। देश की राजधानी होने के चलते दिल्ली में ही भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य व अन्य न्यायाधीश, सेनाध्यक्ष, केंद्रीय कैबिनेट, दिल्ली के उप राज्यपाल, मुख्यमंत्री आदि बहुत सारे देश के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन लोग रहते हैं, राजधानी होने के चलते दिल्ली में राजकीय व अधिकांश केंद्रीय कार्यालय भी है। रोजी-रोटी, शिक्षा चिकित्सा व देश की सबसे ताकतवर सत्ता का मुख्य केंद्र बिंदु होने के चलते ही देश की आज़ादी के बाद से ही दिल्ली की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई थी। दिल?ली में तेजी से बढ़ती आबादी की समस?याओं के समाधान करने के उद्देश्य के लिए वर्ष 1962 में बने दिल्ली के पहले ही मास्टर प्लान में यह सिफारिश की गई थी कि दिल्ली के साथ-साथ इसके आसपास के राज्यों के शहरों को भी एक उप महानगरीय क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए। जिस परिकल्पना को धरातल पर मूर्त रूप देने के लिए वर्ष 1985 में नेशनल केपिटल रिजन प्लानिंग बोर्ड की शुरुआत की गई थी। जिससे इस पूरे क्षेत्र में व्यवस्थित विकास के लिए कार्य योजना बना करके उसका धरातल पर कार्या?वयन किया जा सकें और एनसीआर क्षेत्र में शामिल किसी भी क्षेत्र का विकास अव?यवस्थित ढंग से होने से रोका जा सकें।

दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए ही वर्ष 1985 में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के कुछ जनपदों को मिलाकर के दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तो घोषित कर दिया गया था, लेकिन चार राज्यों व केंद्र की सरकारों के बीच का मामला होने के चलते उस वक्त की गयी पूरी प्लानिंग आज तक भी धरातल पर पूरी तरह से परवान नहीं चढ़ पाई है। जिसका बड़ा खामियाजा दिल्ली व एनसीआर की जनता लगातार भुगत रही है। सिस्टम को सर्वोच्च न्यायालय की बार-बार फटकार लगने के बावजूद भी दिल्ली व एनसीआर के निवासी स्वच्छ पेयजल व स्वच्छ सांसों तक के लिए तरस गये है। आज खराब पानी व प्रदूषित वायु के चलते दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के बड़ी संख्या में पेट, लीवर व फेफड़ों से संबंधित रोगी आसानी से मिल जाते हैं।

हालांकि हम भारतवासियों की यह खूबी है कि हम विपरीत से विपरीत स्थिति में भी उम्मीद की लो जलाकर रखते हैं। जिसके चलते ही आज भी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा व राजस्थान के एनसीआर क्षेत्र के निवासियों का सपना है कि उनको भी एक दिन दिल्ली की तरह ही उच्च गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, बेहतरीन चिकित्सा, विश्वस्तरीय अत्याधुनिक सुविधाएं, रोजी-रोटी, व्यापार करने का अवसर मिलेंगे, जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्र शासित दिल्ली राज्य में कभी एनसीआर के क्षेत्र को जोड़ा गया था, लेकिन अफसोस वह आज तक भी अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया। जिसके चलते ही अब एनसीआर क्षेत्र के एक बहुत बड़े वर्ग का मानना है कि देश का दिल दिल्ली राज्य अपनी सीमाओं का विस्तार करते हुए भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए कार्य करें। लेकिन देश में आये दिन क्षणिक स्वार्थों से पूर्ण राजनीति होने के चलते कभी भी देशहित की इस दूरगामी रणनीति पर किसी भी राजनीतिक दल ने कोई विशेष रणनीति बनाकर कार्य नहीं किया है।

लेकिन जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है, तब से बहुत सारे लोगों के मन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जगह अब बृहद दिल्ली राज्य के निर्माण विचार आने लगा है। क्योंकि फिलहाल केंद्र सरकार के साथ-साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा व राजस्थान में एक ही दल भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार है और सबसे बड़ी बात यह है कि उस राजनीतिक दल के सर्वेसर्वा नरेन्द्र मोदी के पास राजनीति से ऊपर उठकर के देश के नव निर्माण करते हुए, भारत को विश्वगुरु बनाने का जज्बा मौजूद है। लोगों को लगता है कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बृहद दिल्ली या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) अंतरराज?यीय क्षेत्रीय योजना और अत्याधुनिक विकास का एक अद्वितीय उदाहरण बन सकता है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कुछ जनपदों को मिलाकर बनने वाले लगभग 55,083 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का विश्वस्तरीय विकास हो सकता है।

यहां आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई महत्वपूर्ण शहर भी शामिल हैं। एनसीआर के क्षेत्र का आज भी दिल्ली से कई सौ किलोमीटर तक विस्तार है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,1985 के नियोजन बोर्ड के कानून के अनुसार, इस अधिसूचित क्षेत्र में दिल?ली का 1,483 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल आता है। वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलन?दशहर, हापुड, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर जनपद का 14,826 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आता है। वहीं हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूँह, रोहतक, सोनीपत, रिवाडी, झज?जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, महेन?द्रगढ, जींद और करनाल का 25,327 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आता है। राजस?थान के अलवर और भरतपुर का 13,447 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आता है। जिस क्षेत्र को कुछ कम करते हुए भी बृहद दिल्ली राज्य का निर्माण अब इन राज्यों की सहमति से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व आसानी से किया जा सकता है।

वैसे भी देखा जाये तो उस वक्त देश के नीति-निर्माताओं का एनसीआर क्षेत्र बनाने के पीछे मकसद था कि दिल्ली के स्थाई निवासियों के साथ-साथ दिल्ली में आजीविका की तलाश में आ रहे देश के अन्य राज्यों के लोगों को रोजी-रोटी, घर, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, बेहतर कनेक्टिविटी के साथ सार्वजनिक परिवहन जैसी बुनियादों सुविधाओं की कमी का सामना ना करना पड़े। जिसके चलते ही एनसीआर में शामिल होने वाले अन्य राज्यों के कुछ जिलों का विकास राज्य के अन?य जिलों के मुकाबले बहुत तेजी से हुआ। यहां पर लोगों को रोजी-रोटी, घर, बिजली, पानी के साथ-साथ बेहतर प्राथमिक व उच्च शिक्षा, चिकित्सा सुविधा, आधुनिक बस, मेट्रो व रेपिड रेल जैसी विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी की सुविधाएं मिलने से लोगो के रहन-सहन व जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ है। लेकिन एनसीआर के गठन के समय के बहुत सारे उद्देश्य अब भी बाकी है, समय-समय पर राज्यों की आपसी खींचतान के चलते इस पूरे क्षेत्र में काम करने की बहुत गुंजाइश बाकी है। वैसे भी यह पूरा क्षेत्र ऐसा है कि अगर इस क्षेत्र में विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, कानून व्यवस्था बेहतर हो, कल-कारखाने लगें हो, क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रित हो, नदियां स्वच्छ हो, भूजल रिचार्ज करने का कार्य हो, हरित पट्टी व वन्य क्षेत्र विकसित हो, भूकंप रोधी अत्याधुनिक भवनों व इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, विश्वस्तरीय सार्वजनिक परिवहन तंत्र जाल बिछा हुआ हो, शिक्षा, चिकित्सा, रोजी-रोटी की भरमार हो, पूरा क्षेत्र सामरिक दृष्टिकोण से हर वक्त तैयार हो, आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत हो, तो उसका जबरदस्त सकारात्मक प्रभाव पूरे देश की जीडीपी पर पड़ेगा, देश सामरिक रूप से मजबूत होगा। इसलिए बृहद दिल्ली का निर्माण या एनसीआर के पूरे क्षेत्र का नव निर्माण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पास यह शानदार अवसर है।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदों में अष्टादश पुराणों के नाम

(गतांक से आगे...)

यदि ऐसे कथानकों को साद्यन्त इतिहास समझने लगें तो तदन्तर्वर्ती, अध्यात्म आदि विषयों के विमिश्रित अंश में अनेक प्रकार की असंभवता, अश्लीलता, परस्पर विरुद्धता एवं धर्मविरुद्धता का आभास प्रतीत होने लगता है, जिससे अमुक व्यक्ति का विशुद्ध ऐतिहासिक-चरित्र जानना असंभव हो जाता है। इसी प्रकार यदि आध्यात्मिक अंश को मुख्य मानकर तदनुरूप समस्त सन्दर्भ का रूपकप्राय: अर्थ-समन्वय करने लगें तब इतिहास पर पानी फिर जाता है। इस तरह उक्त विमिश्रित संदर्भों के प्रत्येक अंश को पृथक-पृथक किये बिना पुराणों के वास्तविक अर्थों का समझना सर्वथा दुरूह है। हम कतिपय उदाहरण देकर उक्त विशेषता का स्पष्टीकरण करते हैं।

(क) ब्रह्मपुत्र दक्ष ने मनु की कन्या प्रसूति से विवाह किया, उसके सोलह कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें से 13 कन्याएं धर्म को विवाही गई। एक अग्नि को, एक संयुक्त पितरों को और सोलहवीं महादेव को। धर्म के साथ विवाही हुई कन्यायों के नाम- श्रद्धा, मैत्री, दया, शान्ति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितीक्षा, ह्री और मूर्ति थे। आगे धर्म द्वारा उक्त पत्नियों में निम्नलिखित पुत्र उत्पन हुए। श्रद्धा से शुभ, मैत्री से प्रसाद, दया से अभय, शान्ति से सुख, तुष्टि से मुद, पुष्टि से स्मय, क्रिया से योग, उन्नति से दर्प, बुद्धि से अर्थ, मेघा से स्मृति, तितिक्षा से क्षेम, ह्री से प्रश्रय, और मूर्ति से नर नारायण ऋषि। यही दोनों हरि के अवतार होकर यदु और कुरुकुल में कृष्ण तथा अर्जुन रूप में प्रकट हुये थे।

स्वाहा नामक दक्ष की चौदहवीं कन्या में अग्नि द्वारा हवि को खाने वाले पावक, पवमान और शुचि ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए। इन्हीं तीनों पुत्रों से आगे 45 अग्नि नाम के पुत्र हुवे, सो सब मिलाकर पितृपितामह सहित 46 आग्नेयी इष्टिकायें ब्रह्मवादियों द्वारा यज्ञ-विज्ञान में निरूपित की जाती हैं। **क्रमश: ...**

सरोजिनी नायडू

अनन्या मिश्रा

सरोजिनी नायडू किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। वह देश की जानी-मानी हस्तियों में से एक हैं। देश की आजादी के दौरान वह क्रांतिकारी कवियत्री और एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर उभरकर आई। देश के आजाद होने के बाद उनके कंधों पर एक बड़े राज्य की जिम्मेदारी सौंपी गई। सरोजिनी नायडू को यूपी का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। आपको बता दें कि आज के दिन यानि की 2 मार्च को सरोजिनी नायडू का निधन हुआ था। उनका मानना था कि यदि आप दूसरों से ज्यादा ताकतवर हैं, तो आपको दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब मिला था।

हैदराबाद में 13 फरवरी, 1879 को सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था। वह बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि की थीं। वह पढ़ाई में काफी तेज थीं। सरोजिनी के पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय और माता का नाम वरदा सुंदरी था। सरोजिनी के पिता निजाम कॉलेज में रसायन वैज्ञानिक थे।

सरोजिनी नायडू की साल 1914 में पहली बार गांधीजी से लंदन में मुलाकात हुई थी। गांधीजी से मुलाकात के बाद उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। बता दें कि गांधीजी द्वारा निकाली गई दांडी मार्च के दौरान वह गांधीजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलीं। उन्होंने हमेशा गांधीजी के विचारों का अनुसरण कर उसी रास्ते पर चलने लगीं। अपनी सशक्त आवाज और क्रांतिकारी कविताओं से लोगों में आजादी का अलख जगाती थीं। साल 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन में बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान उन्हें कई बार गिरफ्तार भी किया गया।

बता दें कि सरोजिनी नायडू काफी समय तक कांग्रेस की प्रवक्ता रहीं। वहीं साल 1925 में सरोजिनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनीं। इसके अलावा आजादी की लड़ाई के दौरान सरोजिनी ने लिंग भेद मिटाने के लिए कई कार्य भी किए। वहीं देश के आजाद होने के बाद पीएम जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया। वह गोपालकृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक पिता मानती थीं

प्रभावपूर्ण वाणी से लोगों के बीच आजादी की अलख जगाने वाली सरोजिनी को महात्मा गांधी ने नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। उन्होंने अपने लेखन से कई युवाओं को आजादी के लिए प्रेरित किया था। जब भारत में लोग प्लेग महामारी से पीड़ित थे, तो उस दौरान सरोजिनी ने लोगों की सेवा की थी। उनके काम के लिए अंग्रेजी सरकार ने कैसर-ए-हिंद पदक से सम्मानित किया था। लकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सरोजिनी ने व्यथित होकर विरोध में यह सम्मान वापस कर दिया था।

देश की आजादी के 2 साल बाद आज के दिन यानी की 2 मार्च 1949 में लखनऊ के गवर्नमेंट हाउस में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। वहीं उनकी मृत्यु के इतने साल बाद भी लोग उनके योगदान और विचारों को याद करते हैं। वह आज भी महिला सशक्तिकरण का चेहरा हैं।

अमेरिका को भारी पड़ सकती है डोनाल्ड ट्रम्प की शैली?

राजेश बादल

अमेरिका का नया निजाम अवाम पर बेहद भारी पड़ रहा है। वे मतदाता भी सकते में हैं, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प को राष्ट्रपति बनाने के लिए अपना मत दिया था। अपने को संसार का आधुनिकतम लोकतंत्र मानने वाला मुल्क अब घनघोर सामंती घेरे में है। दो पूंजीपति डोनाल्ड ट्रम्प और एलन मस्क अपने राष्ट्र की सियासत को एक ऐसे रास्ते पर लेकर चल पड़े हैं ,जिस पर फिसलन है ,कीचड़ है और अब तक की सारी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। डोनाल्ड ट्रम्प के अमेरिका फर्स्ट के नारे ने बेशक मतदाताओं को लुभाया था, लेकिन अब इस नारे की कलई खुलती जा रही है।

अमेरिकी नागरिक समझ रहे थे कि उनके देश की पूंजी उनके हित में लगाई जाए, यह तो बात समझ में आती है लेकिन हुकूमत उनको ही रोज-रोज परेशान करने लगे, यह उनके लिए तकलीफदेह है। हम जानते हैं कि अमेरिकी लोग संसार में सबसे आरामतलब और सुविधाजीवी हैं। इसलिए उनकी सरकार अब उनसे ही मिनट-मिनट का हिसाब मांग रही है तो वे हैरान और परेशान हैं।

ट्रम्प के दोस्त और वहां के शासकीय दक्षता मंत्रालय के मुखिया एलन मस्क ने दो दिन पहले एक अजीबोगरीब फरमान जारी किया। उन्होंने सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 48 घंटे के अंदर अपने कामकाज की रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। यदि उनकी दक्षता रिपोर्ट संतोषजनक नहीं पाई गई तो नौकरी खोने के लिए तैयार रहना होगा।

यही नहीं, अगर वे अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्रस्तुत करने में नाकाम रहे तो वे अपने आपको नौकरी से बर्खास्त समझ सकते हैं। आपको याद होगा कि अमेरिका में कोविड के प्रकोप के समय से ही बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी घर पर रह कर ही काम कर रहे हैं। उन्हें पूरा वेतन मिल रहा है।

मस्क की चेतावनी उन कर्मचारियों के लिए भी है।

दिलचस्प यह कि डोनाल्ड ट्रम्प ने भी मस्क के इस फरमान को अपना समर्थन दे दिया है। लेकिन मस्क के इस हुक्मनामे से बड़ा बवाल हो गया है। एलन मस्क के इस आदेश का कई सरकारी एजेंसियों ने खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है। मस्क निजी और कॉर्पोरेट शैली में सरकारी कर्मचारियों तथा अधिकारियों से काम लेना चाहते हैं।

सरकारी कर्मचारी इसके लिए तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि पेंटागन, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, नासा, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पुलिस और सेना के लोग इसे कैसे मान सकते हैं? उनका काम न तो प्रोजेक्ट वर्क जैसा होता है और न ही उसे रोज काम के घंटों में बांधा जा सकता है। ट्रम्प सरकार ने बीते दिनों एफबीआई के नए मुखिया काश पटेल को नियुक्त किया है।

पटेल ही इस आदेश के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उन्होंने अपनी जांच एजेंसियों के कर्मचारियों को मस्क के मेल का उत्तर देने से रोक दिया है। पटेल का कहना है कि उनके ब्यूरो की एक प्रक्रिया है, जिसके तहत परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगी जाती है और कर्मचारियों का मूल्यांकन किया जाता है। यही प्रक्रिया मान्य है और इससे हटने का सवाल ही नहीं है।

काश पटेल का पूरा नाम कश्यप प्रमोद विनोद पटेल है और वे पाटीदार समुदाय के गुजराती हैं। उनका परिवार लगभग अस्सी साल पहले गुजरात के आनंद से अमेरिका जाकर बस गया था। वे ट्रम्प के बेहद निकट हैं। उनके तेवर ट्रम्प सरकार के अंतर्विरोधों को उजागर करते हैं। इसी कड़ी में स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग के प्रमुख रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने पहले तो अपने कर्मचारियों से कहा कि वे ईमेल का उत्तर देते हुए अपनी रिपोर्ट भेज दें, मगर बाद में उनका रुख बदल गया। दरअसल विभाग के वकील ने साफ-साफ कहा कि ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

इसी मंत्रालय के कार्यवाहक जनरल काउंसल सीन केवेनी ने अपने बयान में कहा कि वे आहत और अपमानित महसूस कर रहे हैं। केवेनी के अनुसार उन्होंने अपनी विभागीय प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए पिछले सप्ताह सत्तर घंटे तक काम किया है। यह मेल निष्ठा को अपमानित करने वाला है। गौरतलब यह है कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों दलों के कई नेता एलन मस्क के इस रवैये का खुलकर विरोध कर रहे हैं। रिपब्लिकन सीनेटर जॉन कर्टिस ने कहा है कि मस्क का रुख क्रूर और अमानवीय है। सरकार को समझना चाहिए कि कर्मचारी भी इंसान हैं।

उनके परिवार हैं और उन पर बैंक के कर्ज हैं। छंटनी का यह ढंग गलत है। इसी तरह एलन मस्क के विरोध में विदेश और रक्षा विभाग के आला अफसर भी हैं। उन्होंने बाकायदा कर्मचारियों को औपचारिक तौर पर कहा है कि उन्हें मस्क के इस मेल का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। पदभार संभालने के बाद से उन्होंने जितने आदेश जारी किए हैं, उनमें से करीब आधा दर्जन मामलों में अदालतों ने रोक लगा दी है।

ट्रम्प इससे बौखलाए हुए हैं। उपराष्ट्रपति जे। डी। वेन्स और एलन मस्क ने तो न्यायपालिका के खिलाफ आक्रामक अभियान छेड़ दिया है। वेन्स ने कहा कि न्यायपालिका अपनी हद पार कर रही है। उन्होंने यहां तक कहा कि एक जज फौजी जनरल को क्या यह बताएगा कि सैनिक अभियान कैसे चलाया जाता है। न्यायाधीशों को कार्यपालिका के मामलों में टांग नहीं अड़ाना चाहिए।

इसी क्रम में मस्क ने तो यहां तक कह डाला कि एक जज सारी जिंदगी जज कैसे बना रह सकता है? इसके बाद स्वयं डोनाल्ड ट्रम्प न्यायपालिका से मोर्चा लेते नजर आए। उन्होंने कहा कि जिन न्यायाधीशों ने उनके फैसलों पर रोक लगाई है, संभव है कि उन न्यायाधीशों की भी जांच की जरूरत हो। यह मानना जल्दबाजी नहीं होगी कि डोनाल्ड ट्रम्प अपने दूसरे कार्यकाल में अजीब सा व्यवहार करते नजर आ रहे हैं। वे अपने राष्ट्र से ही जैसे रार ठान कर उससे बदला लेने पर उतारू दिखाई देते हैं। वे शुभचिंतक और पिछलग्गू देशों को नाराज कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन अब अमेरिका की अंधभक्त नहीं रही। वह अमेरिका के मसले पर दो-फाड़ हो गई है। कोई नहीं जानता कि ट्रम्प सियासत का कौन सा पाठ लिख रहे हैं?

आज का इतिहास

1956 मोरक्को ने फ्रांस की स्वतंत्रता की घोषणा की।
1965 द न्यूयॉर्क ऑफ़ द रिवाओली थिएटर में द साउंड ऑफ म्यूज़िक फिल्म को परदे पर दिखाया गया।
1970 अफ्रीकी महाद्वीप का देश रोडेशिया (अब जिम्बाब्वे) एक स्वतंत्र गणराज्य बना।
1978 सोवियत अंतरिक्ष यान सोयूज 28, चेक व्लादिमीर रीमेक, सोवियत संघ या संयुक्त राज्य अमेरिका से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति नहीं बने।
1981 पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरवेज फ्लाईट 326 को कराची से उड़न भरने के तुरंत बाद तीन बंदूकधारियों ने अपहरण कर लिया।
1987 अमेरिकन मोटर्स को क्रिसलर कॉरपोरेशन द्वारा अधिग्रहित किया गया।
1991 श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक हुए एक कार बम विस्फोट में देश के रक्षा उपमंत्री रंजन विजयरत्ने सहित 19 लोग मारे गए।
1992 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ने स्टोरों में हर जगह 3.1 रिलीज किया।
1993 सलमान रुश्दी, प्रसिद्ध ब्रिटिश आधारित उपन्यासकार मैरिएन विगिन्स को तलाक देते हैं।
1995 निक लेसेन, ब्रिटिश व्यापारी को बारिंग्स बैंक पीएलसी के पतन के लिए गिरफ्तार किया गया।
1996 रानीबीमा रॉयल कॉलेज श्रीलंका में स्थापित किया गया।
1997 प्रिंस अल-वलीद बिन तलाल, सऊदी अरब के अरबपति एप्पल कंप्यूटर का 5% प्राप्त करते हैं।
1999 नया मंडालय बे होटल और कैसीनो लास वेगास में खोला गया।
2004 इराक युद्ध के दौरान आतंकवादी संगठन अलकायदा ने 170 लोगों की हत्या की, 500 से अधिक घायल।
2009 गिनी-बिसाऊ के राष्ट्रपति, जोआओ बर्नार्डो विएरा बिसाऊ में अपने घर पर एक सशस्त्र हमले के दौरान मारे गए थे।
2010 फ्रांस में रवांडा के राष्ट्रपति जुवेनल हबैरीमना की विधवा अगाथे हाबरिमाना को गिरफ्तार किया गया है। उन पर 1994 के नरसंहार की योजना में मदद करने का आरोप लगाया गया है।
2012 संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी, नासा ने खुलासा किया कि उसने अपनी सुरक्षा को हैकरों द्वारा समझौता किया था। बीते साल में यह 13 बार बना है।

मोदी-योगी के प्रयासों से दिव्य व भव्य महाकुंभ कीर्तिमान बनाते हुए संपन्न

दीपक कुमार त्यागी

महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 26 फरवरी के सूर्यास्त के साथ ही महाकुंभ का समापन हो चुका है,13 जनवरी से 26 फरवरी 45 दिन में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने महाकुंभ में डुबकी लगाई है। महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी के घाटों पर डुबकी लगाने वालों की यह संख्या दुनिया के 193 देशों की आबादी से ज्यादा है। दुनिया में सिर्फ भारत और चीन की आबादी महाकुंभ 2025 में आए श्रद्धालुओं से अधिक है। वैसे भी महाकुंभ 2025 ने देश व दुनिया में विश्व के सबसे प्राचीन सनातन धर्म की महान संस्कृति व अद्भुत परंपराओं की दिव्यता का डंका बजाने का कार्य बखूबी किया है।मोदी व योगी सरकार के प्रयासों से इस बार प्रयागराज में संगम की पावन धारा में देश व दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में बसे हुए लगभग 120 करोड़ सनातन धर्म के अनुयायियों में से लगभग 66 करोड़ से लोगों ने संगम में एक दिव्य अलौकिक डुबकी लगा करके अपने तन-मन की शुद्धि और आत्मा की तृप्ति करने वाला दिव्य अलौकिक अनुभव प्राप्त कराने का कार्य किया है। इस बार महाकुंभ में 75 देशों के डेलीगेट भी आये थे, देश व दुनिया के विभिन्न बड़े सेलिब्रिटी व उधोगपति भी आये थे, जो सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार के मद्देनजर एक बहुत ही अच्छा व सकारात्मक संकेत है।

वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ के दौरान देश में चंद लोगों की एक ऐसी जमात भी खडी हो गयी थी, जिन्हें महाकुंभ में सबकुछ ग़लत होता हुआ ही नज़र आ रहा था। उन लोगों की जमात को महाकुंभ में बेहद खराब व्यवस्था नज़र आ रही थी, गिद्ध दृष्टि के चलते हर तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ नज़र आ रहा था, नदी में जल की जगह मल-मूत्र वाला नालों का जहरीला गंदा पानी नज़र आ रहा था, जगह-जगह भोजन-पानी के लिए तरसते श्रद्धालु नज़र आ रहे थे, महाकुंभ में लूट-खसोट नज़र आ रही थी, पूजा-पाठ की जगह धार्मिक पाखंड नज़र आ रहा था, सुविधाओं के भारी अभाव के चलते तिल-तिल कर मरते लोग नज़र आ रहे थे, जगह-जगह जाम का झाम आदि ही केवल नज़र आ रहा था, जिसका इन लोगों के गैंग ने मीडिया व सोशल मीडिया के विभिन्न ताकतवर प्लेटफार्मों पर पहले ही दिन से अपने चंद क्षणिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए जमकर के फैलाते हुए दुष्प्रचार करने का कार्य किया था। लेकिन 144 वर्ष बाद लगने वाले महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं ने इन दुष्प्रचार करने वाले लोगों के गैंग की एक भी ना सुनी और 13 जनवरी से 26 फरवरी महाकुंभ के समापन तक 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में पहुंच करके स्नान करके दुनिया के किसी भी तरह के आयोजन में सबसे ज्यादा लोगों के पहुंचने का कीर्तिमान बनाकर नया इतिहास रच डालने का कार्य कर दिया। महाकुंभ में दुनिया के 193 देशों की आबादी से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और महाकुंभ नगरी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में इंतजामों की पूरी ही व्यवस्था अकल्पनीय अद्भुत नज़र आयी।

हालांकि अब महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अंतिम स्नान 26 फरवरी 2025 के साथ त्रिवेणी के तट पर 13 जनवरी 2025 से सजा हुआ सनातन धर्म, संस्कृति व परंपराओं के अद्भुत महाकुंभ का मेला नित-नए कीर्तिमान को स्थापित करते हुए दिव्य, भव्य, नव्य व अलौकिक अनुभूति के साथ संपन्न हो गया है। आंकड़ों की बात करें तो महाकुंभ 2025 के समापन तक प्रयागराज में त्रिवेणी के विभिन्न घाटों पर लगभग 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान करके महाकुंभ को विश्व का सबसे बड़ा आयोजन होने का कीर्तिमान भारत के नाम करने का काम कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में यह एक ऐसा रिकॉर्ड बन गया है, जिसको किसी भी देश के द्वारा तोड़ना असंभव है। लेकिन इसके साथ ही महाकुंभ आयोजन की सबसे बड़ी बात यह रही कि 66 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्नान करवाने लिए संगम नगरी को तैयार करने की बहुत बड़ी चुनौती पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से खरे उतरे, उन्होंने इस असंभव कार्य को दिन-रात पूरी टीम के साथ मेहनत करते हुए धरातल पर संभव करके देश व दुनिया को दिखा दिया है।

वैसे देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के प्रयासों से व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी सरकार के प्रचार-प्रसार, प्रयासों के चलते ही महाकुंभ 2025 के शुरू होने से पहले ही लगभग 40-45 करोड़ लोगों के आने का

अनुमान लगाया जाने लगा था, लेकिन समापन महाशिवरात्रि तक संगम तट पर 66 करोड़ से ज्यादा लोगों की भारी भरकम भीड़ उमड़ पड़ी, उस भारी-भीड़ ने देश व दुनिया को दिखा दिया कि अलग-अलग हिस्सों में बसे हुए सनातन धर्मी एकजुट, नियम कायदे कानून पसंद व बेहद ही अनुशासित हैं। तभी तो हजारों किलोमीटर की दूरी से आ कर के बहुत लंबी पैदल यात्रा करने के बाद भी संगम में उन सभी भक्तों के द्वारा अनुशासित होकर के स्नान की एक डुबकी लगाकर के सनातन धर्म, संस्कृति, परंपराओं व ईश्वर भक्ति के अटूट विश्वास को बयां करने का कार्य देश व दुनिया में बखूबी किया है और सनातन धर्म संस्कृति पर आये दिन तरह-तरह से प्रश्नचिन्ह लगाने वाले लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से जवाब दिया है। श्रद्धालुओं का यह कहना बिल्कुल भी ग़लत नहीं है कि प्रयागराज व पूरी महाकुंभ नगरी क्षेत्र केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किये गये विभिन्न कार्यों की दिव्यता की झलक देश व दुनिया तक बयां करने का कार्य बखूबी कर रहा है। देश व दुनिया से आये हुए संत-महात्माओं, नागा साधुओं व सनातन धर्म के अनुयायियों को त्रिवेणी संगम में पुण्य स्नान करा कर उन्हें प्राचीन व आधुनिकता के संगम से परिपूर्ण एक दिव्य अलौकिक आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कराने के लिए योगी सरकार ने कोई कोर-कसर धरातल पर नहीं छोड़ी है। महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं ने अकल्पनीय दिव्य एवं भव्य आयोजन की सराहना करते हुए महाकुंभ के सफल आयोजन को योगी आदित्यनाथ सरकार की एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है।

वैसे भी देश व दुनिया के सनातन धर्म के अधिकांश लोगों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ के प्रयासों के चलते ही इस भव्य दिव्य अद्भुत अलौकिक धार्मिक आयोजन को दुनिया के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। योगी सरकार ने जिस तरह से महाकुंभ में आये लगभग 66 करोड़ से ज्यादा लोगों की सुख-सुविधाओं के लिए भव्य आधुनिक इंतज़ाम किये वह प्रशंसनीय है। उन्होंने पूरे महाकुंभ में मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार आने का रिकॉर्ड बनाकर देश व दुनिया के सनातन धर्मियों को भावनात्मक रूप से यह एहसास करवाने का कार्य किया है कि वह सनातन धर्म की केवल अपने भाषणों में बात ही नहीं करते हैं, बल्कि मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वह देश की मूल आत्मा सनातन धर्म, संस्कृति व उसकी परंपराओं को रोजमर्रा के अपने जीवन में जीने का कार्य करते हैं और उसके प्रचार-प्रसार व हित के लिए निष्ठा व ईमानदारी से धरातल कार्य करते हैं।

लेकिन उसके बावजूद भी वोट बैंक की बेहद ओछी राजनीति के चलते महाकुंभ 2025 के शुरू होने से पहले योगी आदित्यनाथ व उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ लोगों ने अपने निशाने पर लेना शुरू कर रखा था। उन सभी लोगों के गैंग को महाकुंभ में पहले दिन से ही गंदगी के अंबार, अव्यवस्थाओं की भरमार, गंदा जल, कड़ाके की ठंड में स्नान करने से मरते लोग, भूख व प्यास से मरते लोग, अव्यवस्था की भेंट चढ़ते लोगों का जीवन, मरते हुए लोग, संगम में जेसीबी से बहा दी गयी लाशें, रेलवे व बस स्टेशनों आदि पर भारी भीड़ के चलते अव्यवस्था, गंदगी से भरी हुई जन सुविधाएं, प्रयागराज शहर में व उसके चारों तरफ सड़कों पर 300-300 किलोमीटर तक लगा लंबा जाम आदि नज़र आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ में आने वाले आस्था से ओतप्रोत श्रद्धालुओं ने इस गैंग की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया, श्रद्धालु भारी संख्या में प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने दिव्य संगम तट पर योगी सरकार के द्वारा किए गए आधुनिक दिव्य भव्य अकल्पनीय व्यवस्थाओं के अंबार को अपनी आंखों से देखा, उन्होंने संगम रेती पर बसे अद्भुत आध्यात्मिक महाकुंभ नगरी को देखा, अखाड़ों के नगर प्रवेश के भव्य जुलूस को देखा, अखाड़ों के अद्भुत पंडालों को देखा, दिव्य अद्भुत साधु-संतों को करीब से देखा, भस्म लपेट हुए धूनी रमाए नागाओं को तप करते हुए देखा, संगम की रेती में पूजा अर्चना करते हुए आम व खास लोगों को देखा, बहती मां गंगा को देखा, मां यमुना को देखा, संगम स्थल को देखा, सरस्वती कूप को देखा, पौराणिक अक्षय वट को देखा, संगम किनारे लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के दिव्य दर्शन करती भारी-भीड़ को देखा, अखाड़ों के दिव्य अमृत स्नान को देखा, आधुनिक टेंट नगरी को देखा, महाकुंभ में प्रतिदिन औसतन एक करोड़ लोगों को आस्था की डुबकी लगाते हुए देखा, रोज़ाना करोड़ों श्रद्धालुओं की भारी-भीड़ को सुरक्षित ढंग से नियंत्रित करते हुए पुलिस-प्रशासन को देखा, आस्था में ओतप्रोत होकर के दिव्य अलौकिक शक्ति की अनुभूति का अहसास करते लोगों को देखा, पावन दिव्य त्रिवेणी के घाट-घाट पर बिना किसी जाति भेदभाव के स्नान करते हुए सनातन धर्मियों की भारी-भीड़ का अंबार लगते देखा, एक दूसरे लोगों की मदद करते लोगों का व्यवहार देखा, अमीर व गरीब दोनों वर्गों के जो लोगों रोजी-रोटी कमाने की उम्मीद लगा कर आये थे उन लोगों के फलते-फूलते व्यापार को देखा, देश व दुनिया से आये लाखों ऐसे श्रद्धालुओं को देखा जिन्हें पूजा-पाठ व कल्पवास में रहकर शांति मिली रही अपार, सनातन को समझने आये देश व दुनिया के पर्यटकों ने खोज करी हज़ार। लेकिन अफसोस महाकुंभ में बहुत ही शानदार व अकल्पनीय व्यवस्था होने के बावजूद भी कुछ गिद्ध दृष्टि वाले लोग सनातन धर्म व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरोध में बूरी तरह से अंधे होकर के महाकुंभ की व्यवस्था में कमियां ही कमियां गिनाते फिर रहे थे।

लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसी भी आलोचना की परवाह नहीं की और वह महाकुंभ 2025 की व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद कर उसे सफल बनाने में लगे रहे। जिस व्यवस्था को बनाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार व योगी सरकार ने 7500 करोड़ रुपए खर्च किये। जिसके फलस्वरूप ही लगभग 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने महाकुंभ पहुंच करके स्नान करके दुनिया के सबसे बड़े आयोजन का खिताब हासिल करके इतिहास रचने कार्य किया।

आखिर क्यों दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध के खिलाफ है केंद्र सरकार?

कमलेश पांडे

जब राजनीति से भ्रष्टाचार और अपराध खत्म करने के दृष्टिगत केंद्र सरकार ही गम्भीर नहीं है, तब इसे रोकवा पाना न्यायपालिका के लिए कतई संभव नहीं है। चूंकि केंद्र सरकार अपने वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व के इशारे पर हर फैसले लेती है, इसलिए बेलगाम नेताओं को कानूनी नजरिए से बांधने की अधिकांश न्यायिक पहल भी बेकार चली जाती है। सच कहूं तो नक्कारखाने में तूती की आवाज बनकर रह जाती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खुद केंद्र सरकार ने ही दोषी करार दिए गए राजनीतिक नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करने वाली एक अर्जी का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया है। इससे सरकार की बदनीयती समझ में आती है। एक तो वह समय रहते ही कानून नहीं बनाती है और दूसरे जब इसकी मांग उठती भी है तो अपने पूरे सियासी गिरोह की ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। तभी तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस तरह की अयोग्यता तय करना केवल संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। वहां दाखिल अपने हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि अर्जी में जो अनुरोध किया गया है, वह विधान को फिर से लिखने या संसद को एक खास तरीके से कानून बनाने का निर्देश देने के समान है। चूंकि संविधान ने संसद को अयोग्यता से जुड़े ऐसे अन्य कानून बनाने का अधिकार दिया है, जिसे बनाना वह सही समझता हो। सरकार के मुताबिक, संसद के पास अयोग्यता के आधार और उसकी समयसीमा, दोनों तय करने की शक्ति है। ऐसे में आजीवन प्रतिबंध लगाना सही होगा या नहीं, यह पूरी तरह से संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। सरकार का तर्क है कि कानून का स्थापित सिद्धांत है कि दंड या तो समय या मात्रा के अनुसार तय होते हैं। लिहाजा, सजा के असर को एक समय सीमा तक सीमित रखना कोई असंवैधानिक बात नहीं है। बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 संसद, विधानसभा या विधानपरिषद की सदस्यता के लिए अयोग्यता से सम्बन्धित है। अपने हलफनामे में केंद्र ने रेखांकित किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने लगातार यह कहा है कि एक विकल्प या दूसरे पर विधायी विकल्प के असर को लेकर अदालतों में सवाल नहीं उठाया जा सकता। ऐसे में इस विषय पर न्यायिक हस्तक्षेप उचित नहीं है! इसलिए कोर्ट विवेकसम्मत व न्यायसंगत निर्देश दे। बता दें कि वर्तमान में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (1) के तहत, किसी भी नेता को सजा होने के बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोका जाता है। इसलिए केंद्र ने कहा है कि उक्त धाराओं के तहत आजीवन प्रतिबंध लगाना सही नहीं होगा। इस प्रकार सरकार ने कोर्ट के समक्ष तीन बातें स्पष्ट कर चुकी है। पहला यह कि संविधान ने संसद को अयोग्यता से जुड़े कानून बनाने का अधिकार दिया है। दूसरा यह कि यह न्यायिक समीक्षा से जुडी सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों से पूरी तरह से परे है। और, तीसरा यह कि दोषी राजनेताओं पर आजीवन बैन सही है या नहीं, यह सवाल पूरी तरह से संसद के दायरे में आता है। इससे साफ है कि सरकार में शामिल राजनीतिक नेतृत्व अपने दूरगामी राजनीतिक हितों के दृष्टिगत राजनेताओं के खिलाफ सही और तर्कसंगत कानून भी नहीं बनने देता है और जब जब ऐसी बात उठती है तो वह तमाम तरह के किंतु-परन्तु करता है। यही वजह है कि हमारी संसद में गरीबों को छोड़कर हर तरह के लोग मिल जाएंगे।

ट्रंप 2.0 : सबसे सुंदर शब्द टैरिफ के नाम पर जोर का झटका

शंकर अय्यर

दुनिया अनिश्चय के जाल में उलझी है। विभिन्न देशों की राजधानियों और वित्तीय बाजारों को ऐसा लगता है मानो भविष्य को स्थिर कर दिया गया है और वहां के राष्ट्राध्यक्षों व सीईओ वर्ग ने डोनाल्ड ट्रंप के इस कथन को अपना तकिया कलाम बना लिया है कि 'हम देखेंगे कि क्या होता है।' यह ट्रंपवादी रुख उन्हें अपने विचारों की विस्तृत जानकारी देने से मुक्त तो करता ही है, अपनी सुविधानुसार काम करने की स्वतंत्रता भी देता है। राष्ट्रपति बनने के 25 दिन के भीतर ही उन्होंने मौजूदा नियम-आधारित विश्व व्यवस्था को खत्म करने के लिए शब्दों, विचारों और कार्यों की सुनामी ला दी है। आंकड़े इस धमाकेदार कार्रवाई को दर्शाते हैं। 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति ने 20 जनवरी से 14 फरवरी के बीच 64 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं, तथा और भी आदेश आने वाले हैं। 45वें राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने 2017 में 55 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए थे।

ट्रंप द्वारा फैलाई गई अनिश्चितताएं धीमी गति से सामने आ रही हैं। धारणाओं और बारीकियों के टकराव की अभिव्यक्ति के साथ उतार-चढ़ाव ने धारणाओं और अपेक्षाओं को बाधित कर दिया है। चेतना की कई धाराएं हैं। यह इतनी बड़ी हैं कि किसी भी प्रश्न या व्याख्या से पहले आम बात यह नहीं होती कि 'उन्होंने क्या कहा', बल्कि यह होती है कि 'उन्होंने कब क्या कहा'। टैरिफ नीति का लक्ष्य दरों से

सार्वभौमिक टैरिफ और पारस्परिक टैरिफ में परिवर्तन इसे उजागर करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक से कुछ ही घंटे पहले ट्रंप ने पारस्परिक (रेसिप्रोकल) टैरिफ की घोषणा की। इस अस्पष्ट रणनीति को अलग रखें, तो यह विचार अपने आप में नया नहीं है और इसकी उत्पत्ति 1934 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा शुरू किए गए पारस्परिक व्यापार समझौते अधिनियम से हुई है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर यह है कि 1934 में अमेरिका महामंदी का सामना कर रहा था। 2025 में, अमेरिकी आर्थिक वृद्धि 'अमेरिकी अपवादवाद' को उजागर करती है। पारस्परिक टैरिफ का खतरा जटिलताओं में उलझा हुआ है-160 देशों के लिए अमेरिका की सामंजस्यपूर्ण टैरिफ अनुसूची 98 अध्यायों में फैली हुई है, और इसमें आयात के लिए 18,000 से अधिक 10-अंकीय संहिता हैं। सरकारी दक्षता विभाग द्वारा किए गए शुद्धिकरण के वादे की पृष्ठभूमि में इसके अमल की कल्पना करें!

दरअसल, टैरिफ नीति के पीछे वूडू अर्थशास्त्र (एक अपमानजनक शब्द, जो धनी व्यक्तियों के लिए कर में कटौती का पक्षधर होता है) की एक अलग गंध है। ये विचार प्रोजेक्ट 2025 रिपोर्ट से निकले प्रतीत होते हैं। हालांकि रिपोर्ट में भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने को महत्वपूर्ण बताया गया है, लेकिन अध्याय अलग ही राग अलापते हैं। 'निष्पक्ष व्यापार का मामला' शीर्षक अध्याय में, पीटर नवारो तर्क देते हैं कि अगर भारत टैरिफ को अमेरिका के स्तर तक कम कर देता है, तो इससे अमेरिकी व्यापार घाटे में 24 प्रतिशत की कमी आएगी; और अगर अमेरिका टैरिफ को भारत के स्तर तक बढ़ा देता है, तो यह कमी नाटकीय रूप से 88 प्रतिशत होगी। क्या इस दृष्टिकोण के तहत द्विपक्षीय संबंध या व्यापार का विस्तार हो सकता है? स्टील और एल्युमीनियम पर 25 प्रतिशत टैरिफ को ही लें। कई अध्ययनों ने यह स्थापित किया है कि बेस इनपुट पर टैरिफ अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। येल विश्वविद्यालय में लिडिया कॉक्स द्वारा 2023 में किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि प्रतिकूल टैरिफ का रोजगार और उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हालांकि कुछ लोग तर्क देते हैं कि यह बातचीत की रणनीति है, पर कॉक्स बताते हैं कि अस्थायी टैरिफ का भी अर्थव्यवस्था पर लगातार प्रभाव पड़ सकता है। ट्रंप की योजनाएं उनके मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (एमएजीए) के आधार को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अपने चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप ने कहा था कि टैरिफ सबसे सुंदर शब्द है और उन्होंने अमेरिका से वादा किया कि वह चीन पर 60 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे। दरअसल, अक्तूबर 2024 में, ट्रंप ने घोषणा की कि अगर चीन ताइवान में घुसता है, तो वह टैरिफ को 150-200 प्रतिशत तक बढ़ा देंगे। पर ऐसा लगता है कि वह अपने उस रुख से पीछे हट गए हैं।

15 फरवरी तक चीन पर टैरिफ 10 प्रतिशत था, जो अमेरिका के सप्लाई चेन पार्टनर कनाडा और मेक्सिको पर लगाए गए 25 प्रतिशत टैरिफ से कम है। ट्रंप का अपने पड़ोसियों और यूरोप के साथ 'अमेरिकी सामान खरीदें या फिर कुछ और' का दृष्टिकोण अमेरिकी जीडीपी को नुकसान पहुंचा सकता है। फिलहाल ट्रंप का कहना है कि अमेरिकियों के लिए यह दर्द अस्थायी होगा। भू-राजनीतिक मोर्चे पर यह धुरी और भी स्पष्ट है। गुरुवार को ट्रंप ने यूरोप (और कई अन्य सहयोगियों) को यह कहकर चौंका दिया कि वह रूस को जी-8 में वापस लाना चाहते हैं। इस पर चर्चा चल ही रही थी कि ट्रंप ने एक नई गुगली फेंकी। उन्होंने घोषणा की, मैं चाहता हूं कि मेरी पहली बैठक चीन के राष्ट्रपति शी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ हो। और मैं कहना चाहता हूं कि आइए, हम अपने सैन्य बजट को आधा कर दें।

पिछले दिनों जब बेंजामिन नेतन्याहू व्हाइट हाउस आए थे, तब ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका गाजा पट्टी पर कब्जा कर सकता है। इस विचार को अरब जगत ने सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन ट्रंप ने 'ईस्टर्न रिवेरा' योजना पर दोगुना जोर दिया है। उन्होंने फॉक्स न्यूज से कहा कि उनकी योजना के तहत फलस्तीनियों को वापस लौटने का अधिकार नहीं होगा।

दिल्ली की लगातार दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनीं रेखा गुप्ता

अर्चना तिवारी

रेखा गुप्ता का दिल्ली की मुख्यमंत्री बनना भारतीय राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और सशक्तिकरण का प्रतीक है। उन्होंने गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वह दिल्ली की नौवीं और चौथी महिला मुख्यमंत्री बनीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में उन्होंने रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनका मुख्यमंत्री बनना न केवल राजनीतिक समीकरणों को दर्शाता है, बल्कि महिलाओं के बढ़ते प्रभाव का भी संकेत देता है।

रेखा गुप्ता का जन्म 19 जुलाई 1974 को हरियाणा के जींद जिले के जुलाना में हुआ था। उनके पिता बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर थे, जिनका तबादला उनकी बचपन की उम्र में दिल्ली हो गया। उन्होंने दिल्ली में ही स्नातक की शिक्षा पूरी की और फिर एलएलबी और एमबीए की डिग्रियां भी लीं।

रेखा गुप्ता ने 1992 में दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज में पढ़ाई के दौरान छात्र राजनीति में कदम रखा। वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से जुड़ी रहीं और 1996-97 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) की अध्यक्ष बनीं। 2007 में उत्तरी पीतमपुरा से पार्षद चुने जाने के बाद, उन्होंने पुस्तकालय, पार्क और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाओं के विकास पर कार्य किया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी रेखा गुप्ता ने महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए सुमेधा योजना जैसी पहल शुरू की, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को उच्च शिक्षा में सहायता मिली। उन्होंने महिला कल्याण और बाल विकास समिति की प्रमुख के रूप में सशक्तिकरण अभियान का नेतृत्व किया। वह भाजपा महिला मोर्चा की महासचिव और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की सदस्य भी रही हैं।

रेखा गुप्ता की जीत में उनकी आरएसएस से करीबी, जमीनी स्तर पर काम करने का अनुभव और उनकी जातीय पृष्ठभूमि एक महत्वपूर्ण कारक रही। रेखा गुप्ता वैश्य समुदाय से आती हैं, जो दिल्ली में प्रभावशाली है और भाजपा का कोर वोटर माना जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इसी समुदाय से थे, जिससे यह साफ होता है कि इस जातिवर्ग का समर्थन दिल्ली की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता है। हालांकि, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या भाजपा की यह रणनीति कितने लंबे समय तक सफल रहती है और क्या अन्य वर्गों को भी समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना राजनीतिक दलों की ही जिम्मेदारी नहीं है?

भारतीय स्वाधीनता संग्राम में महिलाओं ने बढ़-चढ़कर भूमिका निभाई। सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित और अरुणा आसफ अली जैसी विभूतियों ने सक्रिय राजनीतिक योगदान दिया। 1950 में संविधान लागू होने के बाद महिलाओं को समान राजनीतिक अधिकार मिले, जिनमें मतदान और चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता शामिल थी। इससे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा मिला, जिससे वे शासन और नीति-निर्माण में प्रभावी भूमिका निभाने लगीं।

रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से हराया। यह जीत महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी को दर्शाती है। इस चुनाव में भाजपा को 45% महिला वोट मिले, ये जीत महिला नेतृत्व को अधिक

स्वीकार्यता मिलने का संकेत देती है और महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।

मौजूदा समय में भाजपा और एनडीए की 21 राज्यों में सरकार है, लेकिन इनमें से किसी भी राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं है। राजस्थान और ओडिशा में महिला उपमुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन शीर्ष पद पर महिलाओं की उपस्थिति सीमित है। भाजपा की आखिरी महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थीं, जो 2013 से 2018 तक राजस्थान की मुख्यमंत्री रहीं। रेखा गुप्ता का मुख्यमंत्री बनना इस कमी को पूरा करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

दिल्ली में महिला वोटरों की प्राथमिकताएं पुरुष मतदाताओं से कई मायनों में भिन्न होती हैं। महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, रोजगार के अवसर और वेतन समानता जैसे मुद्दे चुनावों में उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहते हैं। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा सुनिश्चित करना, कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए अनुकूल वातावरण बनाना और घरेलू हिंसा के मामलों पर त्वरित कार्रवाई जैसी समस्याओं का समाधान अपेक्षित है। रेखा गुप्ता का मुख्यमंत्री बनना भारतीय राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का प्रतीक है, लेकिन यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि यह केवल प्रतीकात्मक न रहे। अक्सर, शीर्ष पदों पर महिलाएं आने के बावजूद वे पितृसत्तात्मक राजनीतिक ढांचे के तहत सीमित अधिकारों में काम करती हैं। अगर रेखा गुप्ता को प्रभावी नेतृत्व साबित करना है, तो उन्हें महिला केंद्रित नीतियों को प्राथमिकता देनी होगी।

सबसे पहले, कार्यस्थलों पर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए ठोस उपाय किए जाने चाहिए। इसके तहत महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक कार्यस्थल, समान वेतन, मातृत्व अवकाश और बाल देखभाल सुविधाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अलावा, घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में त्वरित न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करना होगा।

महिला सुरक्षा के संदर्भ में दिल्ली में पहले से ही पिंक बस सेवा और सीसीटीवी कैमरों की पहल की गई है, लेकिन महिलाओं को असल में कितनी सुरक्षा मिल रही है, यह देखना आवश्यक होगा। रेखा गुप्ता की सरकार को महिला हेल्पलाइन सेवाओं को सशक्त बनाना होगा और पुलिस तंत्र को अधिक जवाबदेह बनाना होगा।

इसके अलावा, गरीब और वंचित वर्ग की महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं को सुलभ बनाना भी एक प्रमुख मुद्दा है। महिलाओं को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता उत्पाद और मानसिक स्वास्थ्य सहायता की आवश्यकता है।

भारत में महिला नेतृत्व का इतिहास समृद्ध रहा है, और कई महिला मुख्यमंत्री देश की राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभा चुकी हैं। मायावती, ममता बनर्जी, वसुंधरा राजे, जयललिता और शीला दीक्षित जैसी नेता अपने-अपने राज्यों में प्रभावशाली शासन कर चुकी हैं। इन्होंने विभिन्न विचारधाराओं और राजनीतिक दृष्टिकोणों के साथ प्रशासन चलाया, लेकिन एक बात जो सामान्य थी, वह थी उनकी नेतृत्व क्षमता और प्रशासनिक कुशलता।

रेखा गुप्ता का मुख्यमंत्री बनना महिला नेतृत्व को एक नई दिशा देने वाला कदम है। यह संकेत करता है कि महिलाओं के लिए राजनीति में नए अवसर खुल रहे हैं। हालांकि, राजनीति में महिलाओं के सामने अब भी कई चुनौतियाँ हैं। पुरुष वर्चस्व, संसाधनों की कमी, पारिवारिक और सामाजिक दबाव जैसी बाधाएँ महिला नेताओं के लिए संघर्ष का कारण बनती हैं। अक्सर देखा गया है कि महिलाओं को पार्टी में निर्णायक भूमिकाएँ हासिल करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते हैं। महिला नेतृत्व को मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक दल महिलाओं को निर्णय लेने की भूमिकाओं में अधिक स्थान दें। इसके अलावा, महिलाओं को राजनीतिक शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की ओर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सरकार को भी महिला नेताओं के लिए नीतिगत सहयोग देना चाहिए, जिससे वे अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें।

यदि रेखा गुप्ता इन बाधाओं को पार कर अपनी नीतियों में महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देती हैं, तो यह एक मिसाल बनेगी। इससे न केवल उनके राज्य में महिलाओं को लाभ मिलेगा, बल्कि पूरे देश में महिला नेतृत्व को और बल मिलेगा। यह दिखाएगा कि महिलाएँ राजनीति में न केवल भागीदारी कर सकती हैं, बल्कि निर्णायक भूमिका भी निभा सकती हैं।

हेराफेरी 3 से भी कटा कार्तिक का पत्ता, प्रियदर्शन पहली बार करेंगे किसी सीक्वल का निर्देशन

हिंदी सिनेमा की कॉमेडी फिल्मों में 'हेराफेरी' का अलग ही फैन बेस है। इसमें परेश रावल के निभाए किरदार बाबूराव गणपतराव आप्टे पर जितने मीम्स बने हैं, उतने शायद ही हिंदी सिनेमा के किसी दूसरे किरदार पर बने हों। अगले महीने इस फिल्म की रिलीज के 25 साल पूरे होने जा रहे हैं और इस दिन फिल्म 'हेराफेरी 3' को लेकर भी एक बड़ा एलान होने जा रहा है। इस फ्रेंचाइजी की साल 2006 में रिलीज सीक्वल 'फिर हेराफेरी' को नीरज वोरा ने निर्देशित किया था। अब प्रियदर्शन इसकी तीसरी कड़ी निर्देशित करने जा रहे हैं और ये पहली बार होगा जब प्रियदर्शन अपनी ही किसी फिल्म की कोई सीक्वल निर्देशित करेंगे। फिल्म में एक अहम किरदार कार्तिक आर्यन का भी था, और फिल्म में बाबूराव का किरदार करने वाले परेश रावल ने बाकायदा इसकी सोशल मीडिया पर पुष्टि भी की थी, लेकिन अब कार्तिक आर्यन इस फिल्म का हिस्सा नहीं हैं। परेश के मुताबिक, फिल्म 'हेराफेरी 3' जब निर्देशक फरहाद सामजी के साथ बन रही थी तो उसमें कार्तिक आर्यन को एक नए किरदार के रूप मे लाया जाना था। किस्सा कुछ यूं बना था कि कुछ लोग उसे राजू समझकर पकड़ लाते हैं। फिर फरहाद सामजी की फिल्म से छुट्टी हुई और प्रियदर्शन आ गए तो फिल्म की कहानी भी बदल गई। फिल्म 'हेराफेरी 3' पहले नीरज वोरा ही निर्देशित कर रहे थे तब फिल्म में अक्षय, परेश रावल और सुनील शेट्टी तीनों थे। लेकिन, जब अक्षय और परेश ने ये फिल्म करने से मना किया तो नीरज वोरा फिल्म में जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन और नाना पाटेकर को ले आए थे, लेकिन नीरज के आकस्मिक निधन के बाद से फिल्म लटकी रही।

निर्देशक इंद्र कुमार व अनीस बज्मी के नाम भी फिल्म से जुड़े पर इस साल जाकर ये तय हुआ है कि फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ही करेंगे और फिल्म अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल के साथ ही बनेगी। फिल्म 'हेराफेरी' 25 साल पहले रिलीज हुई थी और इसकी सिल्वर जुबली अगले महीने होली के ठीक बाद मनाने की तैयारी है, उसी दिन फिल्म 'हेराफेरी 3' को लेकर एक बड़ा एलान भी होने वाला है।

सबसे ज्यादा ब्यूटी टाइटल जीत चुकी हैं उर्वशी रौतेला, मॉडलिंग ने खोला अभिनय का रास्ता

बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला अपने अभिनय से ज्यादा अपने ग्लैमर और खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। उर्वशी अपना 31वां जन्मदिन मना रही हैं। अभिनेत्री अपने बेहतरीन स्टाइल से समय-समय पर फैशन गोल्स भी देती रहती हैं। उनकी हर एक तस्वीर सोशल मीडिया पर छाई रहती है। हाल ही में अभिनेत्री डाकू महाराज में नजर आई थीं, जिसमें अपने डांस नंबर से अभिनेत्री ने लोगों को दीवाना बना दिया। उर्वशी रौतेला अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चर्चा में तो बनी ही रहती हैं, लेकिन इसके साथ ही वह अपने फैशन सेंस और पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा बटोरती हैं। अभिनेत्री के जन्मदिन के मौके पर जानते हैं उनसे जुड़ी खास बातें।

बॉलीवुड से साउथ तक छाई उर्वशी

25 फरवरी, 1994 को उत्तराखंड में जन्मीं उर्वशी रौतेला अपने परिवार से पहली शख्सियत हैं, जिन्होंने अभिनय की दुनिया और मॉडलिंग के ग्लैमर वर्ल्ड में किस्मत आजमाई। अपनी खूबसूरती और काबिलियत के बल पर देश से लेकर विदेशों तक में अपनी पहचान बनाने वाली उर्वशी रौतेला का कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं रहा है। उर्वशी के पिता मानव सिंह बिजनेसमैन हैं। उनकी मां मीरा संस्कृति से कुमाऊंनी और एक सफल उद्यमी हैं। वह एक लग्जरी ब्यूटी सैलून की मालिक हैं।

नेशनल लेवल की बास्केटबॉल प्लेयर रह चुकी हैं उर्वशी

उर्वशी रौतेला अपनी खूबसूरती और कमाल की फिटनेस के लिए तो जानी जाती हैं, लेकिन यह बात कम ही लोग जानते हैं कि असल जिंदगी में वह राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। अभिनेत्री ने बास्केटबॉल के लिए विभिन्न प्लेटफार्मों पर अपने राज्य उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया है।

पांच डांस फॉर्म में माहिर हैं उर्वशी रौतेला

उर्वशी रौतेला अभिनय के साथ ही बेहतरीन डांसर भी हैं। उनके कातिलाना डांस मूव्स के पीछे की वजह यह है कि वह एक ट्रेंड डांसर हैं। उर्वशी पांच तरह के डांस फॉर्म्स भरतनाट्यम, कथक, जैज, हिप-हॉप और बेली डांस में माहिर हैं। इसके बाद उर्वशी ने अभिनय में भी अपनी किस्मत आजमाई और उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर बॉलीवुड में अच्छा-खासा मुकाम हासिल किया है। साथ ही अब वह साउथ इंडस्ट्री में भी पैर जमा रही हैं।

सबसे ज्यादा ब्यूटी टाइटल अपने नाम कर चुकी हैं उर्वशी

उर्वशी रौतेला की खूबसूरती के तो सभी कायल हैं। बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने से पहले उर्वशी दो बड़े खिताब को अपने नाम कर चुकी हैं। वह पहली महिला हैं, जिन्होंने 2012 और 2015 में दो मिस यूनिवर्स इंडिया का ताज जीता। इसके अलावा साल 2018 में भी उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सरकार और पर्यटन द्वारा ब्रह्मांड में सबसे कम उम्र की सबसे खूबसूरत महिला के रूप में सम्मानित किया गया था। उर्वशी रौतेला सबसे ज्यादा ब्यूटी टाइटल अपने नाम करने वाली महिला में शुमार हैं।

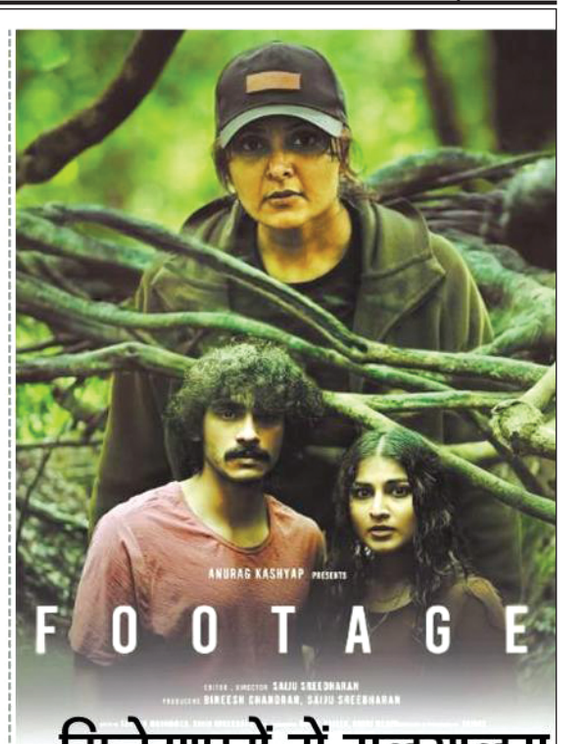

सिनेमाघरों में मलयालम थ्रिलर 'फुटेज' की हिंदी रीमेक रिलीज होगी

फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप मलयालम थ्रिलर फुटेज का हिंदी वर्जन पेश करने के लिए तैयार हैं। इस फिल्म में मंजू वारियर मुख्य भूमिका में हैं। कश्यप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर प्रशंसकों को जानकारी दी। अनुराग कश्यप ने कहा, मैंने 'फुटेज' का मलयालम संस्करण देखा और यह मेरे दिमाग में बस गया। यह फिल्म पिछले साल केरल में रिलीज हुई थी और इसे काफी सराहना मिली थी। अब इसे पूरे देश के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। यह फिल्म सैजू श्रीधरन के निर्देशन में बनी पहली फिल्म है। श्रीधरन को महेशिंते प्रतिकारम और कुंबलंगी नाइट्स जैसी सफल फिल्मों के लिए जाना जाता है। अनुराग कश्यप ने कहा, मलयालम सिनेमा के युवा फिल्म निर्माताओं को नए अंदाज और तकनीक से कहानियां कहते हुए देखना रोमांचक है। वे रूढ़ियों को तोड़ रहे हैं और नई चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं। इस फिल्म में मंजू वारियर के अलावा विशाक नायर और गायत्री अशोक भी नजर आएंगी। कहानी एक यूट्यूब व्लॉगिंग कपल की है, जो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अपने एक हेल्पर की खोज के लिए निकलते हैं। उनकी खोज उन्हें एक अलग द्वीप और एक रोमांचक सफर पर ले जाती है। मंजू वारियर ने कहा, फाउंड-फुटेज फॉर्मेट ने इस फिल्म को खास बना दिया। पूरी कहानी पात्रों को वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए बताई गई, जिससे यह बेहद रोमांचक अनुभव बन गया। फिल्म के हिंदी संस्करण को फ्लिप फिल्म्स, सिनेपॉलिस के साथ साझेदारी में रिलीज करेगी। अनुराग कश्यप हाल ही में टाइगर्स पॉन्ड फिल्म से भी जुड़े, जो इस साल बर्लिनले फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित होने वाली पहली कन्नड़ फिल्म बनी। निर्देशक सैजू श्रीधरन ने कहा, हम बहुत खुश हैं कि अनुराग कश्यप और सिनेपॉलिस हमारी फिल्म को हिंदी दर्शकों तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। गायत्री अशोक ने कहा कि अनुराग कश्यप के समर्थन से यह फिल्म तकनीकी और सौंदर्य की दृष्टि से शानदार साबित होगी, जबकि विशाक नायर ने इसे पूरी टीम की कड़ी मेहनत का परिणाम बताया। फिल्म 7 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

कभी जान्हवी ने उड़ाया था हिमेश रेशमिया का मजाक, सिंगर ने अब किया रिएक्ट

हिमेश रेशमिया की किस्मत के सितारे इन दिनों बुलंदी पर हैं। फिल्म बैडएस रवि कुमार की सफलता को एंजॉय कर रहे हिमेश ने ऐसा भी वक्त देखा है, जब उन्हें खूब ट्रोल किया गया। उनकी आलोचनाएं हुईं और मजाक उड़ाया गया। खुद के बारे में कही गई बातों पर हाल ही में हिमेश ने प्रतिक्रिया दी और बताया कि वे इनसे कैसे निपटते हैं? कुछ वक्त पहले अभिनेत्री जान्हवी कपूर ने सारा अली खान के साथ कॉफी विद करण में शिरकत की थी। इस दौरान जान्हवी ने कहा था कि उन्हें हिमेश के फीड पर जाना और बैकग्राउंड में तंदूरी नाइट्स के साथ उन्हें वर्कआउट करते देखना अच्छा लगता है। उन्होंने उनकी नकल भी की थी। जान्हवी ने हंसते हुए कहा था, यह दुनिया की सबसे अच्छी चीज है। मुझे यह पसंद है।

बहुत पहले छोड़ देता काम करना

हिमेश रेशमिया ने कहा, अगर मुझ पर लोगों की बातों का असर पड़ा होता तो मैं बहुत पहले ही यहां काम करना बंद कर देता। अगर मुझे खुद पर जरा भी शक होता, तो मैं यहां नहीं होता। आपको वही करना चाहिए जो आप कर सकते हैं। भगवान से प्रार्थना करें और अपने रास्ते में आने वाले प्यार को स्वीकार करें। उन्होंने आगे कहा, अक्षय कुमार हमेशा कहते हैं कि हमारे पास ये सभी फॉर्मूले हैं, किसी और की बात सुनो और फिर उसमें सुधार करो। अगर उनके पास एक निश्चित नजरिया है, तो उस पर काम करों और साबित करो।

नजरिए का फर्क है

हिमेश ने आगे कहा, आज मैंने बैडएस रवि कुमार के साथ अपनी मेहनत का फल देखा है। मुझे जो 6 दिखता है, आपको 9 दिखता है, यह नजरिए का फर्क है। किसी की आलोचना का बुरा नहीं मानना चाहिए। जब आशिक बनाया आया, तो बहुत ट्रोलिंग हुई, लेकिन वही लोग क्लबों में नाच रहे थे।

पुष्पा 2 के बाद एक नई फिल्म शुरू कर रहे अल्लू

साउथ सुपरस्टार अल्लू कलाकारों की कास्टिंग शुरू कर अर्जुन पुष्पा दे दी है। उन्होंने फिल्म में अहम रूल की सफलता के बाद अब अपनी अगली फिल्म की तैयारियों में जुट गए हैं। हैदराबाद में फिल्म का प्री-प्रोडक्शन जोरों पर है और फिल्म को लेकर एक नया और दिलचस्प अपडेट सामने आया है। निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास ने फिल्म के लिए भूमिकाओं के लिए कई एक्टर्स से संपर्क किया है। हालांकि, अभी तक इन कलाकारों के नाम या उनके किरदारों का खुलासा नहीं किया गया है। इसकी आधिकारिक पुष्टि निर्देशक की ओर से आनी बाकी है। पुष्पा 2 की तरह, यह भी एक पैन इंडिया फिल्म होगी। निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास ने फिल्म के लिए कलाकारों की कास्टिंग शुरू कर दी है।

गो गोवा गॉन के सीक्वल का निर्देशन करेंगे कुणाल खेमू

बॉलीवुड अभिनेता कुणाल खेमू ने हाल ही में एक साक्षात्कार में कई चीजों पर खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने फिल्म के निर्देशन को लेकर भी अपनी इच्छा जाहिर की। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वह फिल्म गो गोआ गॉन का सीक्वल जरूर निर्देशित करना चाहेंगे।

इस फिल्म में सैफ अली खान मुख्य भूमिका में थे। कुणाल खेमू ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। हम हैं राही प्यार के और राजा हिंदुस्तानी जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम करने के बाद वह बतौर लीड एक्टर कलयुग में नजर आए थे। इसके बाद उन्होंने गो गोआ गॉन, ढोल, गोलमाल 3 और गोलमाल अगेन जैसी कॉमेडी फिल्मों से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई।

गो गोवा गॉन के सीक्वल का करना चाहते हैं निर्देशन

पिछले साल कुणाल ने डायरेक्टर के रूप में अपनी शुरुआत मडगांव एक्सप्रेस नाम की फिल्म से की थी। इस फिल्म में प्रतीक गांधी, अविनाश तिवारी और दिव्येंदु मुख्य भूमिका में थे। बातचीत के दौरान कुणाल ने कहा, मैंने गो गोआ गॉन में सैफ अली खान के साथ काम किया था और मुझे वह अनुभव बहुत पसंद आया था। अगर मुझे मौका मिला तो मैं इसका सीक्वल जरूर बनाऊंगा। साथ ही, मैं अपनी सास शर्मिला टैगोर के साथ भी फिल्म में काम करना चाहूंगा।

फिल्म के दूसरे भाग को लेकर कही ये बात

गो गोआ गॉन के सीक्वल के बारे में बात करते हुए कुणाल ने कहा, सीक्वल बनाना बहुत डरावना होता है, क्योंकि पहले लोग बिना किसी उम्मीद के आते हैं, लेकिन जब उन्हें फिल्म पसंद आती है तो वे सीक्वल के लिए उम्मीदें लेकर आते हैं। इसलिए हम पहले से ही यह सोचते हैं कि दर्शक क्या सोचेंगे। हालांकि, यह भी बहुत रोमांचक भी होता है, क्योंकि अब हमें दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरना होता है। गो गोआ गॉन 2 की घोषणा साल 2018 में की गई थी, लेकिन कुछ वजहों से यह फिल्म अब तक नहीं बन सकी है।

नेहा मलिक ने फैंस को दिया सरप्राइज लॉन्च कर रही हैं पर्सनल एप

अभिनेत्री और मॉडल नेहा मलिक अपना पर्सनल एप लॉन्च करने जा रही हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है। नेहा ने लिखा है, मेरे उन सभी फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज, जो मुझसे सीधे कनेक्ट होना चाहते हैं। नेहा ने लिखा है, मैं अपना पर्सनल एप लॉन्च कर रही हूं। इसके अलावा नेहा ने ईशा गुप्ता के साथ भी तस्वीरें शेयर की हैं और बताया है कि नए वीडियो में दोनों साथ नजर आएंगी। फैंस दोनों को साथ देखने के लिए उत्साहित हैं, फिलहाल ईशा, हनी सिंह के गाने मैनियक में नजर आ रही हैं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

मणिपुर को लेकर अमित शाह ने की अहम बैठक

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए गृह मंत्रालय में बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और अन्य लोग शामिल हुए। पूर्वोत्तर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद यह पहली ऐसी बैठक है। मणिपुर में मई 2023 से जातीय हिंसा जारी है और अब तक वहां 250 लोगों की जान जा चुकी है। अधिकारियों ने मुताबिक, गृह मंत्री ने शनिवार को मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, मणिपुर सरकार, सेना, अर्धसैनिक बल के शीर्ष अधिकारी बैठक में शामिल हुए। एन बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 13 फरवरी को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 2027 तक है और इसे अभी निलंबित अवस्था में रखा गया है। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव भल्ला ने लूटे गए और अवैध हथियारों को जमा कराने की समय सीमा शुक्रवार को छह मार्च शाम चार बजे तक बढ़ा दी है।

पीएम मोदी गुजरात के तीन दिवसीय दौरे पर

अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से गुजरात के तीन दिन के दौरे पर होंगे। वह जूनागढ़ जिले के सासन में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वह जामनगर में रिलायंस फाउंडेशन के पशु बचाव केंद्र वंतारा भी जाएंगे। पीएम श्री सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम के क्रम में वे रविवार को जामनगर स्थित पशु देखभाल केंद्र वंतारा का दौरा करेंगे। वहीं अगले दिन वह जंगल सफारी का आनंद लेंगे। इस बारे में गुजरात के प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख ए पी सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी गिर राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यालय सासन में अपने प्रवास के दौरान विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन करने वाले श्री सोमनाथ ट्रस्ट की एक बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। उन्होंने कहा कि 3 मार्च को प्रधानमंत्री गिर राष्ट्रीय उद्यान में जंगल सफारी का आनंद लेकर अपने दिन की शुरुआत करेंगे, जो एशियाई शेरों का निवास स्थान है।

योगी के कठमुल्ला वाले बयान पर ओवैसी का पलटवार

नईदिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उर्दू पर की गई हालिया टिप्पणियों को लेकर सियासत तेज है। इसी कड़ी में योगी के कठमुल्ला वाले बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इससे साफ है कि यूपी के सीएम को उर्दू नहीं आती। लेकिन वे वैज्ञानिक क्यों नहीं बने इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि यूपी के सीएम जिस विचारधारा से आते हैं, उस विचारधारा से किसी ने भी इस देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। योगी पर हमला जारी रखते हुए ओवैसी ने कहा कि वह गोरखपुर से आते हैं। रघुपति सहाय फ़िराक़ भी उसी गोरखपुर से आते हैं। वह एक प्रसिद्ध उर्दू कवि थे, लेकिन वह मुस्लिम नहीं थे। यह (टिप्पणी) उनकी बौद्धिक क्षमता है। योगी ने विधानसभा की कार्यवाही का उर्दू में अनुवाद करने की मांग करने के लिए मंगलवार को सपा पर निशाना साधा था।

दादागिरी पर उतारू हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप : संजय सिंह

नईदिल्ली। आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यूक्रेन के वलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विस्फोटक बैठक का हवाला देते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत दी है। एक्स पर एक पोस्ट में, सिंह ने पीएम मोदी से कहा कि वह ट्रम्प के पिछलग्गू न बनें और जिस तरह से अवैध भारतीय प्रवासियों को बेड़ियों में जकड़ कर अमेरिका से निर्वासित किया गया, उसके बारे में उनसे बात करें। आप के राज्यसभा सांसद ने पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर के प्रसिद्ध उद्धरण का इस्तेमाल किया- अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, लेकिन दोस्त बनना घातक है- अपनी बात को पुष्ट करने के लिए कि कैसे ट्रम्प प्रशासन ने यूक्रेन को उसके हाल पर छोड़ दिया था। आपको बता दें कि युद्धग्रस्त यूक्रेन को पिछले जो बाइडेन शासन से काफी समर्थन और हथियार मिले थे। संजय सिंह ने वीडियो साक्षा करते हुए लिखा कि इस बातचीत ने साबित कर दिया की ट्रम्प दादागिरी पर उतारू है।

अरोड़ा को चुनाव में उतार आप ने विपक्षी दलों पर बनाई दबाव

चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी (आप) ने लुधियाना पश्चिम उप चुनाव में राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को चुनाव मैदान में उतारकर कांग्रेस, भाजपा व शिरोमणि अकाली दल (शिअद) की परेशानी बढ़ा दी है। अब तीनों विपक्षी दलों पर उप चुनाव में बड़े चेहरे पर दांव खेलने का दबाव है। वर्ष 2022 में भी इस सीट पर आप ने कब्जा किया था और 34.80% वोट शेयर हासिल किया था। ऐसे में अब तीनों दल किसी ऐसे चेहरे की तलाश कर रहे हैं, जो पिछली हार को इस बार जीत में बदल सके। उप चुनाव की अभी घोषणा भी नहीं हुई हैं। आप में सबसे पहले अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, जिससे उसके पास लोगों से संपर्क साधने के लिए भी काफी समय है। पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर कांग्रेस के भरत भूषण आशू रहे थे, जिन्होंने 28.30% वोट शेयर हासिल किया था। पिछले तीन चुनावों से आशू इस सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं।

दुनियाभर के लोग भारत आना चाहते हैं, भारत को जानना चाहते हैं : मोदी

■ 'एनएक्सटी' कॉन्क्लेव 2025 में बोले प्रधानमंत्री-मुझे लुटियंस जमात और खान मार्केट गैंग पर आश्चर्य है

नईदिल्ली। 'एनएक्सटी' कॉन्क्लेव 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के भारत पर आज पूरी दुनिया की नजर है। दुनिया भर के लोग भारत आना चाहते हैं, भारत को जानना चाहते हैं। आज भारत, दुनिया का वो देश है, जहां पॉजिटिव न्यूज लगातार क्रिएट हो रही है। न्यूज मैन्यूफेक्चर नहीं करना पड़ रहा है। जहां हर रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, कुछ न कुछ नया हो रहा है। उन्होंने कहा कि 26 फरवरी को ही प्रयागराज में महाकुंभ संपन्न हुआ है। पूरी दुनिया हैरान है कि कैसे एक अस्थाई शहर में, नदी तट के किनारे करोड़ों लोगों ने स्नान किया।

मोदी ने कहा कि कुछ महीने पहले ही, भारत ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव कराए हैं। 60 साल बाद ऐसा हुआ जब भारत में कोई सरकार लगातार तीसरी बार वापस लौटी है। इस जन-विश्वास का आधार पिछले 11 साल में भारत की अनेकों उपलब्धियां हैं। मुझे विश्वास है कि आपका नया चैनल भारत की वास्तविक कहानियाँ दुनिया तक पहुंचाएगा। बिना कोई रंग दिए आपका ग्लोबल चैनल, भारत की वैसी ही तस्वीर दिखाएगा, जैसा वो है। हमें मेकअप की जरूरत नहीं है।

उन्होंने कहा कि कई साल पहले मैंने वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल का विजन देश के सामने रखा था। आज हम इस विजन को सच्चाई में बदलते हुए देख रहे हैं। आज हमारे आयुष प्रॉडक्ट्स और योग, लोकल से ग्लोबल हो गए हैं। आज भारत के सुपरफूड, हमारा मखाना, लोकल से ग्लोबल हो रहा है। भारत के मिलेट्स-श्रीअन्न भी, लोकल से ग्लोबल हो रहे हैं। भारत, दुनिया का सातवां सबसे बड़ा कॉफी एक्सपोर्टर बन गया है। उन्होंने कहा कि दशकों तक, दुनिया भारत को अपना बैक ऑफिस कहती थी। लेकिन आज, भारत न्यू फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है। हम सिर्फ वर्कफोर्स नहीं, वर्ल्ड-फोर्स हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत बहुत बड़े टारगेट्स रख पा रहा है, उनको अचीव कर रहा है... तो इसके मूल में एक खास मंत्र है। ये मंत्र है- मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। ये कुशल और प्रभावी शासन का मंत्र है। बीते एक दशक में हमने करीब 1,500 ऐसे कानूनों को खत्म किया है, जो अपना महत्व खो चुके थे। इनमें से बहुत सारे कानून अंग्रेजी शासन के दौरान बने थे। उन्होंने कहा कि मुझे उस समय की सरकार और नेताओं से कुछ कहना नहीं है, लेकिन मुझे ज्यादा तो ये लुटियन जमात पर आश्चर्य हो रहा है, ये खान मार्केट गैंग पर आश्चर्य हो रहा है। ये लोग 75 साल तक ऐसे कानून पर चुप क्यों थे। ये हमारी सरकार है जिसने गुलामी के कालखंड के कानून को खत्म किया।

मोदी ने कहा कि एक दशक के भीतर, हमने लगभग 1,500 कानूनों को समाप्त कर दिया जो अपनी प्रासंगिकता खो चुके थे, जिनमें से कई ब्रिटिश काल के थे। बांस पूर्वोत्तर में आदिवासी समुदायों के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। पहले, बांस काटने पर लोगों को जेल हो जाती थी, क्योंकि इसे एक पेड़ माना जाता था और पेड़ से संबंधित कानून इस पर लागू होते थे। हमने औपनिवेशिक काल के ऐसे कानूनों को खत्म कर दिया। अब, आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने जैसी प्रक्रियाएं भी मिनटों में पूरी हो जाती हैं और रिफंड कुछ ही दिनों में जारी हो जाता है।

हम ऐसे भारत के निर्माण में जुटे, जहां किसान समृद्ध और सशक्त हो : प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कृषि और ग्रामीण समृद्धि विषय पर वेबिनार को संबोधित किया। बजट के बाद के इस वेबिनार में पीएम मोदी ने कहा, इस वर्ष का बजट हमारी सरकार के तीसरे टर्म का पहला पूर्ण बजट था। इस बजट में हमारी नीतियों में निरंतरता दिखी ही है, साथ ही विकसित भारत के विजन में नया विस्तार भी दिखा है। विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे भारत के संकल्प बहुत स्पष्ट हैं। हम सभी मिलकर एक ऐसे भारत के निर्माण में जुटे हैं, जहां किसान समृद्ध हो, किसान सशक्त हो।

उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि कोई किसान पीछे न छूटे। हर एक किसान को आगे बढ़ाएं। हमने कृषि को विकास का पहला इंजन मानते हुए अपने अन्नदाताओं को गौरवपूर्ण स्थान दिया है। हम दो बड़े लक्ष्यों की ओर एक साथ बढ़ रहे हैं- पहला, कृषि सेक्टर का विकास और दूसरा, हमारे गांवों की समृद्धि। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 6 साल पहले लागू की गई थी। इस योजना के तहत लगभग पौने 4 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिल चुके हैं। इतनी राशि करीब-करीब 11 करोड़ किसानों के खाते में सीधे पहुंचाई गई है।

उन्होंने कहा कि हमने एक किसान केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, ताकि देशभर के किसानों तक इस योजना का लाभ पहुंच सके। आज भारत का कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है। 10-11 साल पहले जो कृषि उत्पादन 265 मिलियन टन के करीब था, वो अब बढ़कर 330 मिलियन टन से ज्यादा हो गया है। ये हमारी सरकार के बीज से बाजार तक की अप्रोच का परिणाम है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने बजट में पीएम धन धान्य कृषि योजना का एलान किया है। इसके तहत देश के 100 सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले जिले यानी कम उत्पादकता वाले जिलों के विकास पर फोकस किया जाएगा। आज लोगों में पोषण को लेकर काफी जागरूकता बढ़ी है। इसलिए, बागवानी, डेयरी और फिशरी प्रोडक्ट्स की बढ़ती मांग को देखते हुए इन सेक्टर्स में काफी इंवेस्टमेंट किया गया है। फल और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा भी की गई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम आवास योजना-ग्रामीण के तहत करोड़ों गरीबों को घर दिया जा रहा है। स्वामित्व योजना से संपत्ति मालिकों को 'अधिकारों का अभिलेख' मिला है। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप की आर्थिक ताकत बढ़ाई है। हमने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। हमारे प्रयासों से सवा करोड़ से ज्यादा बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं।

बिहार में कांग्रेस को राजद 30 से अधिक सीट देने के मूड में नहीं

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए समय से पहले ही महागठबंधन में सीट बंटवारे की बात गूंजने लगी है। सत्ता के लिए बेचैन महागठबंधन भी इसी परेशानी से जूझ रहा है। कांग्रेस पिछली बार की तरह इस बार भी 70 सीटों का टेर छेड़ चुकी है। जबकि राजद उसे 30 से अधिक देने के मूड में नहीं है। इसके अलावे वाम दलों के भी दावे ज्यादा ही होने की संभावना व्यक्त की जाने लगी है। इसका कारण यह है कि पिछली बार वाम दलों में भाकपा-माले का प्रदर्शन बेहतर ही था। महागठबंधन में मिलीं 19 में 12 सीटें माले ने जीत ली थीं। 2-2 सीटें भाकपा और माकपा ने जीती थीं। इस बार तो भाकपा-माले के दो सांसद भी हो गए हैं। यानी वाम दलों का जनाधार बढ़ा है तो इस बार अधिक सीटों की उनकी दावेदारी तो बनती ही है।

मार्च के मध्य तक मिल सकता है भाजपा को नया अध्यक्ष

नईदिल्ली। भारतीय जनता पार्टी 13 से अधिक राज्यों में संगठनात्मक चुनाव संपन्न होने के बाद 15 या 16 मार्च तक अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा करने के लिए तैयार है। पार्टी सूत्र बताते हैं कि जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी पर फैसला आंतरिक सहमति बनाकर किया जाएगा। एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने संकेत दिया है कि जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था, पार्टी का लक्ष्य इस शीर्ष पद पर एक महिला को नियुक्त करना है, जो संभवत: दक्षिण भारत से होगी ताकि दक्षिणी राज्यों के लोगों को एक मजबूत संगठनात्मक संदेश भेजा जा सके।

यदि दक्षिण की किसी महिला को इस पद के लिए चुना जाता है तो या तो आंध्र भाजपा प्रमुख दग्गुबाती पुरंदेश्वरी या भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और कोयंबटूर विधायक वनथी श्रीनिवासन सबसे संभावित उम्मीदवार के रूप में उभर सकती हैं।

भाजपा, जो परंपरागत रूप से परामर्श के माध्यम से एकता को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती है, अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया में कई कारकों पर विचार कर रही है, जिसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, जाति की गतिशीलता और आगामी चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन शामिल है।

इससे पहले, भाजपा ने कथित तौर पर दिसंबर 2024 तक एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करने का लक्ष्य रखा था। वर्तमान में, जेपी नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता हैं और मोदी सरकार में स्वास्थ्य, रसायन और उर्वरक विभाग रखते हैं। नड्डा 2019 में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष बने। जनवरी 2020 में उन्हें पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया। 2023 में, मई 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले, उनका तीन साल का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा दिया गया था।

सूत्र ने कहा कि दग्गुबाती पुरंदेश्वरी सबसे आगे चलने वालों में से एक हैं। क्षेत्रीय प्रभाव और राष्ट्रीय एकजुटता को संतुलित करने की इच्छुक पार्टी इनमें से एक उम्मीदवार का चयन कर सकती है। पुरंदेश्वरी, लगभग 66 वर्ष की उम्र में, संगठनात्मक मामलों में अपना महत्वपूर्ण अनुभव लेकर, 2014 में कांग्रेस छोड़ने के बाद भाजपा में शामिल हो गईं। वर्तमान में आंध्र प्रदेश में भाजपा प्रमुख के रूप में कार्यरत, उन्हें एक अत्यधिक स्पष्ट महिला नेता माना जाता है। अपने उत्कृष्ट वक्तृत्व कौशल और पांच भाषाओं में प्रवाह के कारण उन्हें %दक्षिण की सुषमा स्वराज% के रूप में जाना जाता है, उन्हें भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच व्यापक स्वीकृति प्राप्त है।

खेल
प्रमुख समाचार

न्यूजीलैंड और भारत के बीच मुकाबला आज

दुबई। अब तक अपराजेय भारतीय टीम का फोकस स्पिन को बेहतर खेलने पर होगा और न्यूजीलैंड के खिलाफ चैम्पियंस ट्रॉफी के आखिरी ग्रुप मैच में रविवार को उन खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है जो अब तक बाहर बैठे हैं। आखिरी ग्रुप मैच जीतने से भारत ग्रुप ए में शीर्ष पर रहेगा। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका या आस्ट्रेलिया से होगा और दोनों के पास बेहतरीन स्पिनर हैं।

भारत ने दोनों मैच जीते हैं लेकिन स्पिनरों ने भारतीयों को परेशान किया है और सेमीफाइनल के लिये क्वालीफाई कर चुकी न्यूजीलैंड टीम इसका फायदा उठा सकती है। भारत के स्टार बल्लेबाजों ने बांग्लादेश के स्पिनरों मेहदी हसन मिराज और रिशाद हुसैन के खिलाफ जोखिम लेने से बचने की रणनीति अपनाई। यही तरीका उन्होंने पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद के खिलाफ भी अपनाया और ये तीनों गेंदबाज काफी किफायती साबित हुए। अब उनके सामने मिचेल सेंटनेर और माइकल ब्रेसवेल की चुनौती होगी जो इस टूर्नामेंट में स्पिन के सामने सबसे कठिन परीक्षा भी रहेगी। दोनों कीवी स्पिनर अच्छे फॉर्म में हैं और दुबई की पिच पर और प्रभावी साबित हो सकते हैं। भारतीय बल्लेबाज स्पिनरों को इक्के दुक्के रन लेकर बड़े शॉट तेज गेंदबाजों के खिलाफ खेलते आये हैं। लेकिन अब उन्हें 20 ओवर सेंटनेर और ब्रेसवेल का सामना करना है जबकि ग्लेन फिलिप्स भी अनियमित स्पिन गेंदबाज हैं। पिछले साल के आखिर में घरेलू टेस्ट श्रृंखला में सेंटनेर और फिलिप्स के खिलाफ भारत का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। भारत को उसमें 0.3 से पराजय झेलनी पड़ी थी और अब यहां इन दोनों के साथ ब्रेसवेल भी हैं जिन्होंने अब तक दो मैचों में 3 . 2 की औसत से ही रन दिये हैं। ऐसे में फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल, पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद शतक जमाने वाले विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को प्रभावी प्रदर्शन करना होगा।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि

नईदिल्ली। मार्च की पहली तारीख पर आम आदमी को महंगाई का झटका लगा है। तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 6 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 1 मार्च से लागू हो गई हैं। हालांकि, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है, क्योंकि 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसी बीच, एविएशन सेक्टर के लिए थोड़ी राहत दी गई है। तेल कंपनियों ने एविएशन टरबाइन फ्यूल के दाम घटा दिए हैं, जिससे हवाई यात्रा सस्ती होने की संभावना जताई जा रही है। तेल कंपनियों ने मार्च महीने की शुरुआत में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में अब 19 किलो के कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम रू.1803, कोलकाता में रू.1913, मुंबई में रू.1755.50, और चेन्नई में रू.1965 हो गया है।

मारुति सुजुकी की फरवरी में बिक्री में मामूली बढ़ोतरी

नईदिल्ली। देश की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने शनिवार को बताया कि फरवरी में उसकी कुल बिक्री सालाना आधार पर मामूली बढ़कर 1,99,400 यूनिट हो गई। कंपनी ने पिछले साल इसी महीने में कुल 1,97,471 यूनिट बेची थीं। मारुति सुजुकी इंडिया ने एक बयान में यह जानकारी दी। कुल घरेलू यात्री वाहन बिक्री पिछले महीने 1,60,791 यूनिट रही, जबकि एक साल पहले इसी महीने यह 1,60,271 यूनिट थी। यह सालाना आधार पर मामूली बढ़ोतरी है। आल्टो और S-Presso जैसी मिनी सेगमेंट की कारों की बिक्री घटकर 10,226 यूनिट रह गई, जो पिछले साल इसी महीने 14,782 यूनिट थी। Baleno, Celerio, Dzire, Ignis, Swift और WagonR जैसी कंपैक्ट कारों की बिक्री बढ़कर 72,942 यूनिट हो गई।

भारत की जीडीपी के आंकड़े देख छिप गया पाकिस्तान!

नई दिल्ली। भारत को तरक्की के मामले में हराने का सपना देखने वाले पाकिस्तान की आवाज नहीं निकल रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पिछले हफ्ते कहा था कि उनका देश तरक्की के मामले में पाकिस्तान को हरा देगा। किसी भी देश की तरक्की उसकी जीडीपी पर निर्भर करती है। भारत की दिसंबर तिमाही में जीडीपी दर 6.2 फीसदी रही है। यह पिछली तिमाही के मुकाबले ज्यादा है। वहीं पाकिस्तान की जीडीपी भारत के मुकाबले कहीं नहीं है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो भारत के मुकाबले यह कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की जीडीपी अभी 3 फीसदी के करीब है। इसमें भी तेजी तब आई है जब उसे आईएमएफ की ओर से लोन दिया गया है। बात अगर वित्त वर्ष 2025 की करें तो आईएमएफ ने पाकिस्तान की जीडीपी वृद्धि दर में कटौती की है। आईएमएफ का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025 के लिए पाकिस्तान की जीडीपी वृद्धि दर 3.2% की जगह 3% रहेगी।

श्रीलंका को आईएमएफ से मिली चौथी किस्त

नईदिल्ली। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने श्रीलंका को 2022 के आर्थिक संकट से उबरने के लिए अपने 2.9 अरब अमेरिकी डॉलर के राहत पैकेज से 33.4 करोड़ डॉलर की चौथी किस्त जारी करने पर सहमति जताई है। आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने श्रीलंका को 48 महीने की विस्तारित निधि सुविधा (ईएफएफ) व्यवस्था के तहत तीसरी समीक्षा पूरी करने के बाद शुक्रवार को चौथी किस्त जारी करने को मंजूरी दी। वैश्विक ऋणदाता ने कहा कि वह संकटग्रस्त देश को लगभग 33.4 करोड़ डॉलर जारी करेगा, जिससे कुल वित्त पोषण लगभग 1.3 अरब डॉलर हो जाएगा। आईएमएफ ने कहा कि श्रीलंका ने कार्यक्रम के तहत अच्छा प्रदर्शन किया है। इस बीच पाकिस्तान का कर घाटा चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों में बढ़कर 606 अरब पाकिस्तानी रुपये (189.45 अरब भारतीय रुपया) हो गया।

आयकर सीमा में बढ़ोतरी लाभकारी साबित होगी

डॉ पीएस वोहरा

आगामी वित्तीय वर्ष के लिए मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट के बाद अब हर तरफ चर्चाएं सिर्फ आयकर में दी गयी छूट के इर्द-गिर्द ही हैं। पर क्या सरकार का यह कदम आने वाले समय में आर्थिक विकास में तेजी दिखायेगा या इसे ऐसी आर्थिक नीतियों के तौर पर जाना जायेगा, जिसमें राजनीतिक दृष्टिकोण बड़ा रुख रखता था, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

प्रारंभिक तौर पर इसमें यह देखने को मिलता है कि आयकर की छूट से व्यक्तियों के पास वित्तीय तरलता में बढ़ोतरी होने के साथ ही प्रत्यक्ष रूप से दो लाभ भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिलेंगे। पहला, लोगों की क्रय क्षमता बढ़ेगी और दूसरा, उनकी बचत बढ़ेगी। तीसरा लाभ यह भी हो सकता है कि कुछ व्यक्तियों को इस वित्तीय बचत से अपने आर्थिक ऋण के भुगतान में भी सहायता मिले, जो पिछले कुछ अरसे से अपने पास कम वित्तीय तरलता से जूझ रहे थे। इस पक्ष को कुछ आंकड़ों से समझते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सामान्य विकास की दर को 10 प्रतिशत के आसपास प्रस्तावित किया है और महंगाई को पांच प्रतिशत से कम। इससे स्पष्ट है कि जीडीपी की वास्तविक विकास दर के छह से सात प्रतिशत के बीच ही रहने की संभावना है। इसलिए मोटे तौर पर यह बात समझ आती है कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की दर को बनाये रखने के लिए क्रय क्षमता में तेजी रखना सरकार की पहली प्राथमिकता है। उधर तस्वीर का दूसरा पक्ष बताता है कि भारत में आयकर देने वालों की संख्या मात्र आठ करोड़ के आसपास है जो कुल जनसंख्या का मात्र पांच प्रतिशत है।

पूर्व में आयकर से कर मुक्त सीमा सात लाख रुपये थी जिसे सरकार ने इस बजट में बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया। परंतु इस आयकर सीमा के अंतर्गत आने वाले करदाता तीन करोड़ या उससे कम ही हैं। उन्हें ही इस कर मुक्त सीमा का लाभ मिलेगा। तो क्या 140 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले देश में आर्थिक विकास की जिम्मेदारी, चाहे क्रय क्षमता बढ़ाने के संदर्भ में हो या आर्थिक बचत के हिसाब से हो, इस छोटे से तबके पर देना तर्कसंगत है? भले ही भारत जीडीपी के हिसाब से विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, परंतु प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से विश्व में बहुत पीछे है। कर मुक्त सीमा में वृद्धि के प्रावधान 2025-26, जो अप्रैल से शुरू होगा, तब से लागू होंगे। आगामी वित्तीय वर्ष की पहली दो तिमाहियों तक इस प्रावधान के सकारात्मक असर देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि दिवाली तीसरी तिमाही में आती है और भारत में क्रय क्षमता का असली शक्ति प्रदर्शन उसी दौरान होता है।

यह भी जानना जरूरी है कि भारत में मध्यवर्गीय व्यक्ति जनसंख्या का लगभग 60 प्रतिशत से अधिक है, जबकि आयकर की इस कर मुक्त सीमा में वृद्धि का लाभ मात्र तीन करोड़ परिवारों को ही होने वाला है। इसलिए इस कर मुक्त सीमा के प्रावधान को पूर्ण रूप से मध्यवर्गीय व्यक्ति के साथ जोड़ना गलत है, क्योंकि यह प्रावधान उच्च मध्यवर्गीय व्यक्ति को ही प्रभावित करते हैं। वर्ष 2017-18 से 2024-25 तक वेतनभोगी व्यक्तियों की वित्तीय आय में छह प्रतिशत से अधिक की कमी देखी गयी है, जबकि स्व-नियोजित रोजगार वेतनभोगी व्यक्तियों की आय में नौ प्रतिशत से अधिक की। जिन आयकर दाताओं को इस आयकर सीमा के प्रावधानों से लाभ होगा, वे कुल वेतनभोगियों का मात्र 25 प्रतिशत हैं। बाकी बचा 75 प्रतिशत वह वेतनभोगी तबका है, जिसके वेतन में पिछले छह-सात वर्षों में बहुत अधिक वृद्धि दर्ज नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, महंगाई की दर का चार से पांच प्रतिशत के बीच में बने रहना, तथा खाद्य पदार्थ की महंगाई का आठ प्रतिशत के स्तर पर पहुंचना कष्टदायक है, क्योंकि जीएसटी की दरों में परिवर्तन की कोई आशा अभी नहीं दिखती है। सरकार ने बजट प्रस्तुत करते समय आयकर की इस प्रमुख सीमा के प्रावधान में वृद्धि से तकरीबन एक लाख करोड़ रुपये के आर्थिक नुकसान को भी प्रस्तावित किया है।

नगर पालिक निगम जगदलपुर के नवनिर्वाचित महापौर संजय पांडे एवं पार्षदगण ने शपथ ली।

समारोह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव मा.उपमुख्यमंत्री अरुण साव, मंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप विधायक नीलकंठ टेकाम, नारायण चंदेल, कमलचंद्र भंजदेव सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी गण, ऊर्जावान कार्यकता गण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

रामू जगदीश रोहरा ने धमतरी महापौर पद की शपथ ली

मंत्री टंकराम वर्मा, सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी पूर्व मंत्री विधायक अजय चंद्राकर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सव्वनी, प्रदेश मंत्री विकास महतो,प्रदेश कार्यालय प्रभारी नरेश गुप्ता, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य प्रीतेश गांधी सहित पदाधिकारी रहे मौजूद।

कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण सदैव हुए अहित के कारण अब जनजातीय समाज डीलिस्टिंग चाहता है : भाजपा

अम्बिकापुर की महापौर के नगर निगम दफ्तर के गंगाजल से शुद्धिकरण और स्वयं को पहली हिन्दू महापौर बताने संबंधी बयान को लेकर कांग्रेस खिसियाहट में खम्भा नोच रही है: सिंहदेव

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने अम्बिकापुर नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर मंजूषा भगत के नगर निगम दफ्तर के गंगाजल से शुद्धिकरण संबंधी बयान को लेकर कांग्रेस द्वारा किए जा रहे अनर्गल प्रलाप को कांग्रेस की बौखलाहट बताते हुए कहा है कि महापौर श्रीमती भगत ने जब यह कहा कि वह पहली हिन्दू महापौर हैं, तो कांग्रेस इस पर बवाल मचा रही है। दरअसल कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण सदैव से जनजातीय समाज का अहित हुआ है। इसलिए जनजातीय समाज अब चाहता है कि डीलिस्टिंग हो।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री सिंहदेव ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जनजातीय और अल्पसंख्यक समाज, दोनों का गलत तरीके से लाभ लेते आ रहे हैं। इससे जनजातीय समाज में काफी आक्रोश है। डीलिस्टिंग की आवाज को कांग्रेस अब दबा नहीं सकती। सरगुजा का जनजाति समाज अपने सांस्कृतिक, धार्मिक एवं प्रगति के अधिकार को लेकर सजग है। श्री सिंहदेव ने कहा कि सत्ता पर अपना ही एकाधिकार मानने वाली कांग्रेस के लोग अपनी करारी हार की खिसियाहट में गंगाजल से शुद्धिकरण की बात को लेकर अब खम्भा नोचने में लगे हुए हैं।

जिन कांग्रेसियों को श्री राम के अस्तित्व, श्री राम के मंदिर, सनातन संस्कृति और महाकुम्भ के दिव्य

आयोजन तक से तकलीफ होती है, उन कांग्रेसियों को यह बात कभी समझ ही नहीं आएगी कि गंगाजल, गौमूत्र, गोबर सनातन परंपरा के अनुष्ठानों के मूल में है, इस समझ के लिए उन्हें हिन्दू पूजा पद्धति को समझना होगा। श्री सिंहदेव ने कहा कि अपनी करारी हार को विनम्रता से स्वीकार करने के बजाय कांग्रेस अपने सत्तावादी अहंकार में जनादेश का घोर अपमान करते हुए अब महापौर श्रीमती भगत के बयान को साम्प्रदायिक रंग देकर अपने तुष्टीकरण के एजेंडे पर चल रही है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस का समूचा राजनीतिक चरित्र और इतिहास इस बात का गवाह है कि वह जब सत्ता में रहती है तो धर्मांतरण और भ्रष्टाचार को शह देकर तुष्टीकरण और लूट-खसोट का एजेंडा चलाती है और जब वह सत्ता से उखाड़ फेंक दी जाती है तो साम्प्रदायिक और भ्रष्ट तत्वों को आगे करके सामाजिक विद्वेष पैदा करके अपने राजनीतिक स्वार्थ साधने के गर्हित हथकण्डों का इस्तेमाल करके वातावरण में विष घोलने का काम करती है। श्री सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस धर्मांतरण और भ्रष्टाचार के खिलाफ उठने वाली हर एक आवाज को दबाने के तमाम नाजायज उपक्रम करती है। श्री सिंहदेव ने कहा कि जो भी धर्मांतरण के पैरोकार हैं, वह सब महापौर श्रीमती भगत के बयान की आड़ लेकर धर्मांतरण और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। लेकिन, कांग्रेस के लोगों को दीवार पर लिखी यह इबारत अच्छी तरह पढ़ लेनी चाहिए कि अब अपने इन गर्हित इरादों में वे कतई कामयाब नहीं हो पाएगी।

अभियंता संघ के अधिवेशन में नई भर्ती, ओपीएस की पुरजोर उठी मांग

ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ेंगी चुनौतियां, नवाचारों के लिए रहें तैयार: एम डी कटियार

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री एस के कटियार ने कहा है कि ऊर्जा क्षेत्र में आने वाले दिनों में चुनौतियां और बढ़ेंगी और ऐसे में युवा अभियंताओं को नवाचार के लिए तैयार रहना होगा।छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल अभियंता संघ के एक दिवसीय प्रादेशिक अधिवेशन एवं असाधारण सभा में मुख्य अतिथि श्री कटियार में कहा कि टीम वर्क के बगैर हमारी सफ्लता सुनिश्चित नहीं हो सकती इसलिए हमें मिलकर चलना होगा । अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र मड़वा के सीनियर क्लब में आयोजित कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एवं ट्रांसमिशन कंपनी के एमडी श्री राजेश कुमार शुक्ला ने अपने

संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि वरिष्ठ इंजीनियरों के अनुभव और युवा अभियंताओं की ऊर्जा के समन्वित प्रयास से हम अपनी प्रगति को सुनिश्चित कर सकते हैं। अधिवेशन में प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर राजेश पांडे, महासचिव मनोज वर्मा,कार्यक्रम संयोजक एच एन कोसरिया, कोषाध्यक्ष श्री शशांक श्रीवास्तव प्रमुख रूप से उपस्थित थे। अध्यक्ष राजेश पांडे ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए पॉवर कंपनी में पुरानी पेंशन योजना की बहाली, कनिष्ठ स्तर पर नई भर्ती, अंतर कंपनी ट्रांसफर पर रोक समेत कई मांगे कंपनी प्रबंधन के समक्ष रखी। महासचिव मनोज वर्मा ने बताया कि अधिवेशन की शुरुआत में अभियंताओं के प्रेरणा भारत रत्न इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की प्रतिमा का अतिथियों द्वारा अनावरण किया गया । एवं वरिष्ठ अभियंताओं सर्वश्री पी एन सिंह, सुरेन्द्र तिवारी,शरद श्रीवास्तव, मुकेश नाहर,संजय तैलंग, पी के खरे , सुनील विश्वास,राकेश शर्मा ,अनिल व्यास, एस के बंजारा, प्रवीण श्रीवास्तव, विनय पांडेय, विनोद अग्रवाल, सी एम बाजपई , मोहम्मद शाहिद खान को अभियंता के रूप में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। अधिवेशन में ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे नवाचारों के लिए अभियंताओं की भूमिका तथा दक्षता सुधार पर विशेष तौर पर चर्चा की गई।

एनआईटी रायपुर के शोध क्षेत्र को इसरो के साथ जोड़ने की पहल करेंगे: डॉ. सोमनाथ

रायपुर। एनआईटी रायपुर के सेंटर ऑफ स्पेस एंड इंटरप्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन (कोसाइन) ने 28 फरवरी 2025 को एक फैकल्टी इंटरेक्शन सेशन का आयोजन किया, जिसमें इस विचार पर मंथन किया गया कि संस्थान राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशनों में कैसे योगदान दे सकता है और छत्तीसगढ़ में अंतरिक्ष तकनीक पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे बढ़ावा दे सकता है। यह सत्र विशेष रूप से उन फैकल्टी सदस्यों के लिए डिज़ाइन किया गया था जो या तो पहले से ही अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या काम करने के इच्छुक हैं। इस सत्र के मुख्य वक्ता इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एस. सोमनाथ रहे, उन्होंने उपस्थित फैकल्टी सदस्यों के साथ अंतरिक्ष विज्ञान और इसके विभिन्न

पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। डॉ. सोमनाथ ने संकाय सदस्यों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत की और विशिष्ट शोध समस्याओं के समाधान का सुझाव दिया जिन्हें अभिनव तरीके से संबोधित किया जा सकता है। उन्होंने एनआईटी रायपुर के फैकल्टी मेंबर्स और इसरो विशेषज्ञों के बीच बातचीत को सुविधाजनक बनाने में अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया, साथ ही कहा कि वे इसरो केंद्रों में वैज्ञानिकों के साथ बैठकों की व्यवस्था करने और संकाय सदस्यों के लिए देश भर में प्रयोगशालाओं का दौरा आयोजित करने में सहायता करेंगे। इस पहल का उद्देश्य एनआईटी रायपुर के शोध क्षेत्र को इसरो के साथ जोड़ना और राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशनों में प्रभावशाली योगदान को प्रोत्साहित करना रहा।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

विज्ञान ने जीवन को सुगम बनाया: डॉ प्रीति मिश्रा

रायपुर। डॉ राधाबाई शासकीय नवीन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ के भौतिक शास्त्र विभाग द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर

विभाग की छात्राओं ने होलोग्राम, टू स्टेप रेल्वे ट्रेक एक्सिडेंट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तथा लेक्टरीक प्रोजेक्ट आन रोड पर आधारित चलित मॉडल प्रदर्शित किये।मॉडल के निर्णायक डॉ शुभ्रा मिश्रा सहायक प्राध्यापक भौतिक शास्त्र विभाग, शासकीय नवीन महाविद्यालय गुढियारी तथा डॉ प्रीति श्रीवास्तव विभागाध्यक्ष वनस्पति विज्ञान विभाग डॉ राधाबाई शासकीय नवीन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर थी। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ प्रीति मिश्रा ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विज्ञान ने हमारे जीवन में कई बदलाव किए हैं,जैसे कि परिवहन,चिकित्सा,कृषि, उद्योग,मनोरंजन वगैरह। विज्ञान ने हमें चांद तक पहुंचाया है और मंगल की भी झलक दी है। विज्ञान ने भाप इंजन को विद्युत इंजन में बदला है। विज्ञान ने हमें हाई-स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल करने का सुहिलियत दिया है। विज्ञान ने कई तरह के रोगों का इलाज संभव बनाया है। विज्ञान ने कृषि को विकसित क्षेत्र बना दिया है।

आयुक्त मिश्रा ने गोंदवारा ब्रिज सफाई का किया निरीक्षण

रायपुर। आज स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2025 के तैयारी अभियान का नगर निगम आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा ने नगर निगम जोन क्रमांक 1 के क्षेत्र में भारत माता चौक गुढ़ियारी से लेकर वसंत विहार गेट नम्बर 3 के आसपास से होकर गोंदवारा ब्रिज तक मार्ग सफाई का प्रत्यक्ष अवलोकन नगर निगम जोन 1 जोन कमिश्नर हितेन्द्र यादव सहित कार्यपालन अभियंता डी. के. पैकरा, जोन स्वास्थ्य अधिकारी खेमलाल देवांगन की उपस्थिति में किया. आयुक्त अबिनाश मिश्रा ने अधिकारियों को स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान की पुख्ता तैयारियों के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दिए. आयुक्त ने गोगांव के शीतला तालाब में प्रगतिरत विकास और सौंदर्यीकरण सम्बन्धी कार्यों का प्रत्यक्ष अवलोकन कर कार्यों को सतत मॉनिटरिंग कर जनहित में जनसुविधा विस्तार की दृष्टि से तय समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करवाने के निर्देश दिए. आयुक्त ने रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सम्बंधित अधिकारियों को गोगांव शीतला तालाब में अच्छी प्रकाश व्यवस्था शीघ्र करवाने के निर्देश दिए.

कांग्रेस के पास हार को छिपाने के लिए कोई बहाना नहीं: साव

रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि, नगरीय निकाय और त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव का परिणाम भाजपा के पक्ष में आया है। दोनों चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफहुआ है। वे ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों में क्रमशः पराजित हुए हैं। और उनके पास हार को छिपाने का कोई बहाना नहीं बचा है। अगले 4 साल नए बहाने खोजे कांग्रेस। अब चूंकि सारे बहाने खत्म हैं और करारी हार पर जवाब नहीं दे पा रही है कांग्रेस, इसलिए ईडी के नाम पर भ्रम फैलाकर राजनीति कर रहे हैं कांग्रेसी। जबकि ईडी साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई कर रही है। श्री साव ने आगामी बजट को लेकर कहा कि, यह वर्ष छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष है। और सोमवार को विधानसभा में विकसित छत्तीसगढ़ और विजन 2047 को अचीव करने वाला बजट पेश होगा। उन्होंने कहा कि, सबका साथ, सबका विकास हमारा मूल मंत्र है। हर वर्ग के कल्याण के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास पर केंद्रित यह बजट होगा। और इस वर्ष को रजत जयंती वर्ष घोषित किया है। इन सब चीजों पर फोकस करते हुए यह बजट होगा। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि, जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। यहां के आम लोग महसूस कर रहे हैं कि, उनके जीवन में खुशहाली और तरक्की आई है। श्री साव ने कहा कि, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व विकास कार्य हुआ है।

विशेषज्ञ चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे नये अपडेट को किया साझा

रायपुर। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में मेडिसिन विभाग द्वारा वार्षिक राज्य स्तरीय सम्मेलन मेडिसिन अपडेट 2025 का आयोजन महाविद्यालय परिसर स्थित स्व. अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में शनिवार को सफ्लतापूर्वक किया गया। इस सम्मेलन में राज्यभर के मेडिसिन विभाग के नामी चिकित्सकों ने जुटकर चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे नये अपडेट को साझा किया। मेडिसिन अपडेट 2025 का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉ. जी. बी. गुप्ता (पूर्व कुलपति आयुष विवि), विशिष्ट अतिथि डॉ. शशांक गुप्ता (पूर्व विभागाध्यक्ष मेडिसिन विभाग नेहरू चि. महाविद्यालय), डीन मेडिकल कॉलेज डॉ. विवेक चौधरी, अम्बेडकर अस्पताल अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर एवं आयोजन अध्यक्ष तथा विभागाध्यक्ष मेडिसिन डॉ. डी. पी. लकड़ा की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीन डॉ. विवेक चौधरी ने कहा कि यह कार्यक्रम चिकित्सा के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति पर चर्चा करने के लिए अग्रणी विशेषज्ञों, चिकित्सकों और शोधकर्ताओं को एक साथ लेकर आया है। अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर ने कहा कि यह सभी चिकित्सकों के लिए चिकित्सा जगत में भविष्य की चुनौतियों के साथ-साथ अवसरों पर चर्चा करने का एक शानदार अवसर है।

गिरौदपुरी धाम में 4 से 6 मार्च तक होगा गुरूदर्शन मेला

रायपुर। गिरौदपुरी धाम में इस वर्ष तीन दिवसीय गुरूदर्शन मेला का आयोजन 4 से 6 मार्च 2025 तक होगा। मेला आयोजन समिति की बैठक धर्मगुरु गुरुबालदास साहेब की अध्यक्षता में जिला पंचायत बलौदाबाजार के सभागार में संपन्न हुई, जिसमें मेले की तैयारियों और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं व सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में राजमाता गुरु प्रवीण माता जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब, राजमहंतगण, पूर्व विधायक डॉ. सनम जांगड़े, कलेक्टर दीपक सोनी, एसएसपी विजय अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। धर्मगुरु गुरुबालदास साहेब ने बैठक में कहा कि बाबा गुरु घासीदास जी के सम्मान में आयोजित गिरौदपुरी मेला सबकी भागीदारी से शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न किया जाएगा। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि किसी भी प्रकार की अप्रिय गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल ने कहा कि गिरौदपुरी मेला श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, जहां लाखों लोग आते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा विशाल जैतखाम के निर्माण के साथ अन्य सुविधाएं भी विकसित की गई हैं। वहीं, आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि मेला समिति के सदस्य मेले की अवधि में व्यवस्थाओं की निगरानी करें और मेले के बाद सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराएं।

25 मार्च 2025 के पूर्व पदोन्नति आदेश जारी करने प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने की मांग..

बिना प्राचार्य बने हर माह सैकड़ों की संख्या में रिटायर्ड हो रहें वरिष्ठ व्याख्याता एवं प्रधान पाठक

रायपुर/ छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा तथा छत्तीसगढ़ राज्य सर्वशासकीय सेवक अधिकारी-कर्मचारी पदोन्नति संघर्ष मोर्चा ने प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यरत हजारों नियमित व्याख्याता तथा प्रधान पाठकों की प्राचार्य पदोन्नति की आवाज़ को शासन तक पहुंचाने कारगर पहल की हैं। प्रदेश में विगत 11 वर्षों से 3500 से अधिक शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल में प्राचार्य के रिक्त पदों पर पात्रता रखने वाले नियमित व्याख्याता तथा प्रधान पाठक माध्यमिक शाला (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) की प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं हुई हैं। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को पत्र प्रेषित कर प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में 3500 से अधिक रिक्त प्राचार्य के समस्त पदों पर व्याख्याता तथा प्रधान पाठकों से प्राचार्य पदोन्नति का आदेश 25 मार्च 2025 के पूर्व जारी किए जाने की मांग की हैं । प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने बताया कि प्रत्येक माह सैकड़ों की संख्या में वरिष्ठ व्याख्याता एवं प्रधान पाठक बिना प्राचार्य बने रिटायर्ड होते जा रहें है। विगत तीन माह के भीतर 31 दिसम्बर 2024, 31 जनवरी 2025 एवं 28 फ़रवरी 2025 को 300 से अधिक वरिष्ठ व्याख्याता टी-ई- संवर्ग एवं प्रधान पाठक टी-ई संवर्ग बिना प्राचार्य पद पर पदोन्नति पाएं विभाग से रिटायर्ड हो गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में पूरी निष्ठा से 35 वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण करने के बाद भी तथा प्राचार्य पद का वेतन पाने के बावजूद सैकड़ों वरिष्ठ व्याख्याता एवं प्रधान पाठक प्राचार्य पद पर पदोन्नति पाएं बिना अपने मन में टीस लिए गहरी पीड़ा के साथ रिटायर्ड हो गए। अनेक वरिष्ठ व्याख्याता तथा प्रधान पाठक वर्षो इंतजार करते-करते बिना प्राचार्य पद पर पदोन्नति पाएं स्वर्ग सिधार गए। 35 वर्ष से 40 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद भी प्रदेश के सैकड़ों वरिष्ठ व्याख्याता तथा प्रधान पाठकों को प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं मिली। इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं। आगामी 31 मार्च 2025 को 100 से अधिक वरिष्ठ व्याख्याता टी-ई संवर्ग तथा प्रधान पाठक टी-ई संवर्ग रिटायर्ड होने वाले हैं, यदि 25 मार्च 2025 के पूर्व प्राचार्य पद पर पदोन्नति आदेश जारी हो जाता हैं तो ये सभी वरिष्ठ व्याख्याता तथा प्रधान पाठक अपने सेवाकाल के अंतिम दिन प्राचार्य पद से रिटायर्ड होंगे, जो सरकार की ओर से उनके जीवन के लिए एक अनमोल तोहफा और सेवा के लिए सम्मान साबित होगा। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा तथा छत्तीसगढ़ राज्य सर्वशासकीय सेवक अधिकारी-कर्मचारी संघर्ष मोर्चा के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के टी एवं ई संवर्ग के व्याख्याता तथा प्रधान पाठक से प्राचार्य पदोन्नति किए जाने के लिए हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ से लेकर सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली तक न्याय के लिए गुहार लगाई गई। छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा तथा छत्तीसगढ़ राज्य सर्वशासकीय सेवक अधिकारी - कर्मचारी पदोन्नति संघर्ष मोर्चा ने पूर्व में मुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री , स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय तथा विभागीय उच्चाधिकारियो से मुलाकात कर अनेकों बार ज्ञापन सौंप कर प्राचार्य पदोन्नति के लिए मांग की, किंतु सरकार के द्वारा प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के समुचित सुधार के लिए बेहद जरूरी इस प्राचार्य पदोन्नति की मांग को तरजीह नहीं दी गई, नतीजा हर वर्ष सैकड़ों की संख्या में व्याख्याता तथा प्रधान पाठक बिना प्राचार्य पदोन्नति के सेवानिवृत होते चले गए, अनेकों व्याख्याता तथा प्रधान पाठक प्राचार्य बनने का सपना लिए स्वर्ग सिधार गए।

लाइनमेन का सहयोग व सम्मान करें ताकि बिजली व्यवधान के निदान में वे शांत मन से कार्य कर सकें

रायपुर। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी एवं भारत सरकार के मार्गदर्शन में 4 मार्च, 2025 को मनाये जाने वाले पांचवे लाइनमेन दिवस के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री भीमसिंह कंवर ने संदेश जारी किया है। उन्होंने बिजली लाइन पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों से यह अपील की है कि अपनी सुरक्षा का ध्यान रखे। वहीं उन्होंने आम जनता से अपील की है कि लाइनमेन साथियों के

जोखिमपूर्ण कार्य तथा आपातकाल में उनकी सेवाओं का सम्मान करें। लाइनमेन दिवस पर जारी अपने संदेश में एमडी डिस्ट्रीब्यूशन श्री भीमसिंह कंवर ने कहा है कि लाइनमेन हमारी विद्युत प्रणाली में नींव की तरह काम करते हैं। जिसके ऊपर पूरी डिस्कॉम के कार्य की सफलता की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नियमित भर्ती, संविदा नियुक्ति तथा आउटसोर्सिंग आदि माध्यमों से लगभग 11 हजार कर्मी लाइनों पर काम कर रहे हैं, जो दिन-रात उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति में योगदान देते है। श्री भीमसिंह ने लाइन स्टॉफ तथा उनके परिवारजनों को उनके समर्पण तथा जोखिमपूर्ण सेवाओं के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होंने कहा कि लाइन स्टॉफ चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर परिस्थिति में लाइन में जरा भी खराबी आने पर, चाहे वह तार टूटने की खराबी हो, वितरण ट्रांसफार्मर का डीओ जल जाने की खराबी हो या फिर सबस्टेशन में कोई दिक्कत आये, इन सबको ठीक करने में लगे रहते हैं। लाइनमेन का तात्पर्य हेल्पर आदि लाइन स्टाफ भी है। साथ ही लाइन में निकलने वाले एई, डीई व अन्य अधिकारी भी इसमें भूमिका निभाते है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.